

**ANNUAL REPORT (1964-65) OF THE OIL AND NATURAL GAS COMMISSION**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SARDAR IQBAL SINGH) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Oil and Natural Gas Commission for the year 1964-65, under sub-section (3) of section 23 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959. [Placed in Library, *See* No. LT-5640/66.]

**ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1964-65) OF THE HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD., RASAYANI AND RELATED PAPERS**

SARDAR IQBAL SINGH: Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers, under sub-section (1) of section 619-A of the Companies Act, 1956 :—

- (i) Fourth Annual Report and Accounts of the Hindustan Organics Chemicals Limited, Rasayani, for the year 1964-65, together with the Auditors' Report on the Accounts.
- (ii) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library, *See* No. LT-5639/66 for (i) and (ii).]

**ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1964-65) OF THE PYRITES AND CHEMICALS AND DEVELOPMENT COMPANY LTD., NEW DELHI AND RELATED PAPERS**

SARDAR IQBAL SINGH: Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following papers, under sub-section (1) of Section 619-A of the Companies Act, 1956 :—

- (f) Fifth Annual Report and Accounts of the Pyrites and Chemicals Development Company Limited, New Delhi, for the year 1964-65, together with the Auditors' Report on the Accounts.
- (ii) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library, *See* No. LT-5636/66 for (i) and (ii).]

**ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1964-65) OF THE INDIAN OIL CORPORATION LTD. AND RELATED PAPERS**

SARDAR IQBAL SINGH : Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the

following papers, under sub-section (1) of section 619-A of the Companies Act, 1956 :—

- (i) Sixth Annual Report and Accounts of the Indian Oil Corporation Limited for the year 1964-65, together with the Auditors' Report on the Accounts' and the comments of the Comptroller and Auditor-General of India thereon.
- (ii) Review by Government on the working of the Corporation.

[Placed in Library, *See* No. LT-5638/66 for (i) and (ii).]

**ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1964-65) OF THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LTD., AND RELATED PAPERS**

SARDAR IQBAL SINGH: Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following papers, under sub-section (1) of Section 619-A of the Companies Act, 1956 :—

- (i) Ninth Annual Report and Accounts' of the Fertilizers Corporation of India Limited, for the year 1964-65, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor-General of India thereon.
- (ii) Review by Government on the working of the Corporation.

[Placed in Library, *See* No. LT-5637/66 for (i) and (ii).]

**THE GOVERNMENT SAVINGS CERTIFICATE RULES, 1965**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification G. S. R. No. 1889, dated the 16th December, 1965, publishing the Government Savings Certificates Rules, 1965, under sub-section (3) of section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959. [Placed in Library, *See* No. LT-5665/66.]

**(i) THE PUBLIC DEBT (AMENDMENT) RULES, 1966****(ii) THE PUBLIC DEBT (COMPENSATION BONDS) AMENDMENT RULES, 1966**

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under subsection (3) of section 28 of the Public Debt Act, 1944:—

(i) Notification G.S.R. No. 109, dated the 13th January, 1966, publishing the Public Debt (Amendment) Rules 1966. (ii) Notification G.S.R. No. 110, dated the 13th January, 1966, publishing the Public Debt (Compensation Bonds) Amendment Rules, 1966. [Placed in Library. See No. LT-5555/66 for (i) and (ii).]

**ALLOTMENT OF TIME FOR CONSIDERATION OF THE MOTION RE. FOOD SITUATION IN THE COUNTRY**

MR. CHAIRMAN : I have to inform Members that under rule 172 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I have allotted six hours for the consideration of the Motion regarding: the food situation in the country.

**RE. RAID ON AIJAL IN MIZO HILLS DISTRICT OF ASSAM BY ARMED PEOPLE**

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar) : Sir, may I respectfully draw your attention and the attention of this House including that of the Government to news of a most disquieting nature about certain happenings in the Mizo Hills District of Assam ? It is reported that in the early hours of the 1st of March a band of 10,000 armed people (It is P.T.I. report) raided Aijal, which is the headquarters of the Mizo Hills District, and Lungleh, a sub-divisional headquarter, and overran some security posts also at Lungleh. It is reported that they have taken possession, after killings or capturing the guards, of the arms and ammunition stored in the armoury and the money kept in the treasury. It is reported that the Sub-divisional Officer of Lungleh, Mr. R. V. Pillai, is missing. Two men of Assam

Rifles are missing. It is also reported that some of the security men, who were reported to be missing earlier, are really dead—they have been killed by these armed hostiles. They have, as I said, taken possession of the arms. This is news of an extremely disquieting nature. Sir, this is the beginning of guerilla warfare of a particular type, with which the world has become familiar during the last thirty years, where the rebels manage to snatch away the arms of the authorities, and with these they go on building up their strength. Therefore, Sir, I request you to request the Government to make a detailed statement on this issue so that the fears of the Members of Parliament in the matter of loss of lives and property and the country's security are allayed.

MR. CHAIRMAN. We have received your notice and we will pass it on to the Government, and then we will get their reactions. Now I would ask the Prime Minister to reply to the debate on the motion of Thanks on the President's Address.

**MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS**

**प्रधान मंत्री तथा परमाणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** श्रीमान्, पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं इस सदन में पूरे वक्त रह नहीं सकी माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के लिये, लेकिन हमने उसकी पूरी नोटिंग रखी थी और रोज शाम को मुझे मालूम होता था कि क्या-क्या बातें यहाँ पर हुई हैं। उनकी आलोचना, उनके सुझाव, बहुत गौर से मैंने देखे हैं। सबका जवाब तो यहाँ देना असम्भव होगा लेकिन कुछ का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी और जिनका यहाँ जवाब नहीं दे सकती हूँ उन पर भी गौर होगा और अगर उचित कार्यवाही कुछ हो सकती है तो वह होने की हमारी कोशिश रहेगी।

एक कायदा रहा है हमारी पार्लियामेंट में कि चाहे आलोचना भी हो तो वह देश की उन्नति के खयाल से, जनता की भलाई के

### [श्रीमती इन्दिरा गान्धी]

खयाल से माननीय सदस्य अपने विचार रखते हैं? मेरी आशा है कि यही भावना देश के प्रति रखते हुये हम अपनी एकता कायम रखेंगे और मेरी कोशिश यहाँ रहेगी कि सारे देश में भी ऐसा एकता की भावना बने और जो बड़े-बड़े प्रश्न हमारे सामने हैं उनका सामना हम इसी भावना से कर पायें।

बहुत-सी बातें यहाँ कहीं गई हैं। मैं तो चाहती हूँ कि शासन में हम किसी तरह से कार्य-क्षमता लाने की कोशिश करें क्योंकि जब तक यह नहीं होगा तब तक कोई भी कार्यक्रम पुरो तरह से पूरा नहीं हो सकता है और न जो हम स्तर ऊँचा करना चाहते हैं राष्ट्रीय जीवन का, वही हो सकता है। जिस देश को भी हम देखें, जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने प्रगति की है, तो हम देखेंगे कि चाहे वह किसी भी विचारधारा के हों, समाजवादो हों या कोई और, कपिटलिस्ट हों, जिन्होंने कार्य-क्षमता को तरफ ध्यान दिया है तो वे देश आगे बढ़ सके हैं। इसलिये हमारा ध्येय है कि हम अपने शासन के तरीके बदलें, अपने काम को पक्का करने की कोशिश करें और काम की बुनियाद को और मजबूत बनायें।

इस सदन में बहुत से सदस्यों ने, श्री मारि-स्वामी ने और औरों ने भी, भ्रष्टाचार के बारे में इस चर्चा में भी और पहले भी अनेक दफा बातचीत की है। मैं मानती हूँ कि यह अयोग्यता की उपज है, यह सच जरूर है कि हमारे देश में, जैसे कि दूसरे देशों में, कुछ न कुछ भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जिस तरह से यह बात घड़ी-घड़ी उठाई जाती है इसको मैं बहुत जायज नहीं समझती हूँ। अक्सर कोई खास बुनियाद न होते हुए भी बात बढ़ाने की कोशिश होती है और मैं मानती हूँ कि इससे हमारे देश को लाभ नहीं बल्कि हानि ही होती है। लेकिन यह कहते हुये मैं फिर से दुहराना चाहती हूँ, जो मैंने अनेक बार यहाँ कहा, कि हमको पूरी तहकीकात करनी चाहिये और जहाँ भी कुछ गलत बात का सबूत हो उसको

पूरे तौर से देखना चाहिए और जो भी कार्य-वाही उचित हो वह करनी चाहिए। और हम जो ओहदों पर हैं, राजनैतिक जीवन में हैं, हमारा भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपना स्तर ऊँचा रखें और कोई ऐसा गलत-फहमियाँ और गलत बातें न आने दें। काम में जो रुकावटें अक्सर होती हैं उनके कारण भी ये बातें बढ़ती हैं और खाली बढ़ती नहीं हैं बल्कि यह भी एक भावना जनता में आती है कि शायद इस देरी का कारण या गलत सुझाव या गलत नतीजे पर पहुँचने का कारण भी भ्रष्टाचार ही है चाहे वह हो नहीं। तो इस तरफ हमें ध्यान देना है।

इस वक्त जो सब से गम्भीर समस्या देश के सामने है वह देश की आर्थिक स्थिति की है। इसके बारे में मुझे बहुत अधिक तो नहीं कहना है क्योंकि आप सबकी काफी मालूम भी है और हमारे फाइनेंस मनिस्टर ने इस पर अपने भाषण में काफी चर्चा की। हम नहीं मानते हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि एक देश जो हिन्दुस्तान जैसा गरीब है वह इतना खर्चा अपनी फीज पर करे, यह हमारी उन्नति में बाधा डालता है, लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि इसमें हम लाचार हैं और अगर हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो हमें इसका खर्चा तो कुछ न कुछ रखना ही है और इसी दृष्टिकोण से हमारे रक्षा खाते की तस्वीर बनाई गई है। लेकिन मुझे खुशी है कि यह जो नक्शा बना है उसमें भी काफी धन रखा गया है विकास कार्य के लिये, कारखानों के लिये, अस्पताल, सड़कों और मकान के लिये। एक बड़ी समस्या हमारे सामने है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम हम बढ़ने न दें। मुझे मालूम है कि वह बढ़ रहे हैं और उनकी वजह से जनता को काफी कठिनाई है। श्री नफीसुल हसन और औरों ने इस बात पर यहाँ जोर दिया था। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कामतों की स्थिरता की तरफ पूरी कोशिश करें। यह तभी हो सकता है जबकि हमारी पैदावार बढ़े और इसीलिये हमारी

नीति है कि अपने उत्पादन को हर एक तरह से बढ़ायें और उत्पादन के लिए प्रेरणा दें।

कई क्षेत्रों में आज कमी है और आलोचना हुई है कि आज जो कंट्रोल हैं हम उनको हटाएं। माननीय सदस्य जानते हैं कि कंट्रोल कोई अपनी मर्जी से रखा नहीं जाता है। कभी-कभी ऐसी समस्या होती है कि उसके बिना काम चल नहीं सकता है। आज कंट्रोल ज्यादातर खाद्य की वस्तुओं पर है। हो सकता है कि दूसरी वस्तुओं पर भी करने को जरूरत हो। लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि जब तक पूरी जरूरत न हो ऐसा कोई कार्य नहीं होगा।

खाद्य क्षेत्र जो बने हैं, उस पर भी काफी आलोचनाएं हुई हैं और यह भी मैंने यहां कहा है—और जगह भी कहा है—कि इस बात पर पूरी तरह से हम विचार करेंगे। लेकिन संग-संग हमें सोचना चाहिये कि अगर ये एकदम से हटा दिये जायें तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। काफी खतरे इसमें हैं। तब भी हम पूरी तौर से इसकी जांच करेंगे। लेकिन अगर बदलना भी हो, कोई दूसरा सिस्टम जाना हो, तब भी किस वक्त हो, किस तरह से हो, यह एक बहुत गौर से सोचने की बात है जिससे इसे बदलने के वक्त, कम से कम कठिनाई देश के लोगों को हो।

यहां पर आनन्द चन्द जो, श्री मुकुट बिहारी लाल जी, श्री मेहता और श्री गोविन्दन् नायर ने हमारे गोदामों में जो बरबादी होती है उसकी चर्चा की थी। मैंने कुछ उसके बारे में जांच करवाई है और मुझे मालूम हुआ है कि जो बरबादी हुई है यह बहुत ही कम है। आप जरा देखें, कितना अनाज गोदामों में है। अनाज की बरबादी का जो परसेन्टेज है वह काफी कम है लेकिन तब भी हमें बहुत कोशिश करनी चाहिये कि यह जो कुछ जाया हो रहा है इसको भी हम पूरी तौर से बंद कर सकें। यह ऐसा समय है कि हम सबको देखना है कि किस तरह से हम जैसे एक-दूसरे

की खुशी में साथ देते हैं वैसे ही इस कठिनाई में भी साथ दें। जहां पर दूसरे प्रान्त के लोगों की कठिनाई है वहां पर उनकी कैसे मदद कर सकें यह हमें विचार करना है, हर एक जगह के लोगों को विचार करना है।

पिछले महीने कुछ बारिश हुई और मैं सुनती हूँ कि उससे गेहूं कुछ अधिक हमें शायद मिले। परन्तु चावल अभी भी कम है और कमी रहेगी। कितनी भी हम कोशिश करें आज हम अधिक चावल ला नहीं सकते। दुर्भाग्य से जो यहां बारिश की कमी हुई वह कमी और जगह भी हुई है जहां-जहां चावल का उत्पादन होता है और दुनिया के बाजार में भी आज चावल काफी नहीं है। यही कारण है कि मैंने अपील की थी कि जो चावल खाने वाली जनता है वह इस समय में दूसरे खाने की चीजों का उपयोग करे। मुझे मालूम है कि यह आसान नहीं है, जिनको एक वस्तु की आदत है उनके लिये कठिन है लेकिन तब भी कठिनाई के समय दूसरे प्रान्तों ने भी ऐसा किया है, दूसरे देशों ने तो बहुत जोरों से ऐसा किया है। मैं नहीं मानती कि हिन्दुस्तानी किसी भी तरह उन दूसरे देशों के लोगों से कम हैं और इसलिये हमको इस समय भी, खास तौर से जो हमारे सदस्य उन प्रदेशों से आते हैं जहां यह कठिनाई है उनको चाहिये कि यह कार्य अपने हाथों में लें।

जहां पर भी कमी है वहां सहायता के कार्य हो रहे हैं, रोजगार बढ़ाने के लिये उपाय बूढ़े जा रहे हैं और अनाज का जो हिस्सा है वहां पर वह हर महीने बढ़ाया जा रहा है। अनाज का बंटवारा भी अब पहले से अच्छा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जा रही हैं। एक और बड़ी कठिनाई हमारे सामने है, वह है पानी की कमी। दुर्भाग्य से मैं समझती हूँ कि आने वाले गर्मी के महीनों में भी शायद यह कठिनाई कुछ जगहों में बढ़े। प्रदेश सरकारों को इसकी खबर है और मेरी पूरी आशा है कि ऐसा होने से पहले वे पानी के लिये पूरा प्रबन्ध कर सकेंगे।

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

हमने अपने प्लानिंग कमीशन से कहा है कि इन सब बातों पर वे प्रथम विचार करें और यह देखें कि किस तरह से ये कठिनाइयां दूर हों—दूर तो नहीं हो सकती हैं लेकिन उनका सामना किस तरह से जोरों से हो सकता है—जिससे जनता को कम-से-कम तकलीफ पहुंचे।

कुछ लोगों ने, श्री लोकनाथ मिश्र और खांडेकर जी ने, कुछ जिक्र किया उड़ीसा में और प्रदेशों में जो मृत्युएं हुईं। इसकी हमको कोई खबर नहीं। जो हमने जांच करने की कोशिश की उसका भी यही जवाब आया है कि वहां उनको ऐसी मृत्युओं की कोई खबर नहीं है, और मैं प्रार्थना करूंगी माननीय सदस्यों से कि ऐसी बातें कहने से, जब तक कि पूरी तौर से जांच न हो, देश में भी एक अजीब हालत पैदा होती है, और खास तौर से बाहर देशों में तो, आप सभी स्वीकार करेंगे कि, आजकल एक अजीब व गरीब हमारे देश का प्रचार हो रहा है और पूरा प्रयत्न हमें करना है कि हिन्दुस्तान की एक जो तस्वीर बाहर है वह किसी तरह से बिगड़े नहीं।

बाहर से हम मदद ले रहे हैं। हम खाद्य की वस्तुओं के लिये भी मदद ले रहे हैं, और चीजों के लिये भी मदद ले रहे हैं और इस बारे में भी काफी आलोचना हुई है। यह मदद जो है यह सब देश एक-दूसरे से लेते हैं। हिन्दुस्तान के पास इतने कम साधन, इतने कम रुपये, होते हुए भी हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं क्योंकि दोस्ती के लिये यह सहयोग बहुत आवश्यक है। इसी भावना से हम भी दूसरों से मदद ले रहे हैं। कोई भीख मांगने की भावना हमारे सामने नहीं है। लेकिन वह भावना हम कैसे बना सकते हैं अगर घड़ी-घड़ी हम कहते रहे "हम भीख मांग रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं।" तो जरूर यह बात बाहर दुनिया में भी फैलेगी। हमको एक देश से सहयोग करने के दृष्टिकोण से इसको देखना है। एक और बात मैं इसके

बारे में कहना चाहती हूँ, वह यह है कि यह जो एक-दूसरे को मदद देने के कार्यक्रम है, इसमें यह "एड" शब्द अंग्रेजी में प्रयोग होता है, यह बहुत अच्छा शब्द नहीं है क्योंकि अधिकतर जो हमें मिलता है वह "एड" नहीं है बल्कि "लोन" है। हमको उसका पूरा कर्जा वापस करना होता है और हम उसको अदा कर रहे हैं, हम मुफ्त में नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितना भी हमको बाहर से मिलता है, चाहे उसमें आप पी० एल० 480 की जो रकम है उसको भी शामिल करिये, तब भी जो हमारी पूरी चेष्टा है उसका यह खाली चौथाई हिस्सा बाहर से आता है। तो ज्यादा जोर हम अपने ऊपर डाल रहे हैं, हम ज्यादा बोझ उठा रहे हैं बनिस्वत इसके कि जो हमें बाहर से मिल रहा है। इस तस्वीर को हमें अपने सामने, देश के सामने, बहुत सफाई से रखना है। बाहर के देशों ने जिन्होंने हमारी मदद की उनके हम सब आभारी हैं और अनेक बार मैंने और औरों ने इसकी चर्चा की है। साथ ही साथ मैं दोहराऊंगी कि, जैसा मैंने अभी कहा, मुझे दुःख है कि बिदेशों में यह जो एक अजीब व गरीब तस्वीर भूखे हिन्दुस्तान की फैल रही है, इसमें थोड़ा हमारा भी कसूर है। लेकिन उस चीज को रोकने की अब हमारी कोशिश होनी चाहिये। मैंने कहा है कि हम मदद चाहते हैं, हमें उसकी जरूरत है और हम मदद लेंगे, लेकिन साथ-साथ यह भी कहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ कि देश की इज्जत को मैं किसी तरह से बेचूँ। मैं तैयार नहीं हूँ किसी तरह से हमारे राष्ट्र का मान कम हो और अगर ऐसी कोई भी बात उठेगी तो उसका मुकाबला मैं मानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ।

अक्सर यह भी चर्चा होती है कि ये-ये बातें किसी देश ने कहीं। अब जो देश कुछ देगा उसको पूरा हक है कि वह दे या न दे, यह हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी देश से ले लें, और उनको पूरा अधिकार है कि वे जो उसके बारे में कहना चाहें या कोई

रुकावट डालना चाहें, या हमें कुछ मुझाव देना चाहें, तो पूरा उनको अधिकार है। हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं, हमारे सामने सवाल यह है कि हम उसको मंजूर कर रहे हैं या नहीं। इस बात को अक्सर हम भूल जाते हैं यहां पर।

दूसरी बात इस विषय में मुझे कहनी है वह यह है कि जो मदद हम ले रहे हैं वह आजकल की कठिनाइयों को देखकर ले रहे हैं, आयन्दा अगर हमको जरूरत नहीं होगी तो नहीं लेंगे। हम जो मदद ले रहे हैं, खाली हम ही नहीं ले रहे हैं, दुनिया के बहुत देश ले रहे हैं। हमें जो देश मदद देता है चाहे वह कितना ही बड़ा देश क्यों न हो, धनी क्यों न हो, जिस तरह से हमको उनकी मदद की जरूरत है, उसी तरह से उनको भी हमारी जरूरत है। तो आजकल दुनिया का हर एक देश एक-दूसरे पर थोड़ा बहुत निर्भर रहता ही है। क्योंकि हम ऐसी कठिन समस्या में फंस हुए हैं और हमने देखा कि जरूरत के वक्त हमारे पास ऐसे साधन नहीं हैं, खाम तोर पर ऐसी आवश्यक वस्तुएं, जैसे खाता है और जिसके लिए हमको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है कि हम इस चीज के बारे में आत्म-निर्भरता की तरफ चलने का पूरा प्रयत्न करें। इसके लिए हमारे पास जो पुराने साधन हैं उनका उपयोग करें और साथ ही साथ फटिलाइजर जैसे नये-नये साधन हैं, जिनका दूसरे देश उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग भी हम अपने किसान भाइयों को करना सिखायें।

यहां पर फटिलाइजर डील के बारे में आलोचना हुई है। कभी-कभी हमें मदद लेने के बारे में ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जिनमें अगर कोई खर्च बुराई न हो, तो देश की कोई कमी पूरी करने के लिए लेने में कोई हानि नहीं है। मैं यह मानती हूँ कि हमने जो इस वक्त समझौता किया है उसका मतलब यह है कि बजाय इसके कि हम उस खाद को बाहर के देशों से खरीदें, हम उसको

अपने ही स्वदेशी कारखानों में बना सकें। हमारे ही मजदूर कारखानों में काम करके और यहां का कच्चा माल इस्तेमाल करके उसको तैयार करें। यह बात सब क्षेत्रों में जरूरी है कि हम अपने साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करें। हम अपनी पूंजी, अपना प्रबन्ध, दक्षता, टैकनीक, प्रतिभा, स्वदेशी माल और अपनी मशीन का इन सब चीजों का पूरे तोर पर उपयोग करें।

यहां पर श्री अण्णादुरे और प्रा० वाडिया जी ने शायद यह कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वे नफा नहीं बनाते हैं। यह बात पूरे तोर से ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि 37 प्रोजेक्ट्स में से केवल 4 ऐसे हैं जिनमें नफा नहीं हो रहा है। हमें पूरे तोर से जोर देना है कि जो ठीक नहीं चल रहे हैं उनको ठीक तरह से चलायें। जो बात मैंने पहले कही थी सरकारी कार्यों को चलाने के बारे में, वह बात इन सब कामों पर भी लागू होती है और उसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि वह सब ठीक तरह से चलें। हमें उपभोक्ता उद्योगों को बढ़ाना है और सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे रही है और देने की योजना है। जब हम इन बातों की तरफ मोचते हैं, तो हम अक्सर एक-एक बात को अलग-अलग लेते हैं और सारे देश की पूरी तस्वीर को नहीं लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत-सी चीजों में कमियां हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि शायद बहुत-सी गलतियां भी हुई हैं क्योंकि हमारे देश ने एक नया कदम उठाया था। कुछ लोगों ने कहा कि जापान और हमारे छोटे देशों ने काफी तरक्की की है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि उन देशों के सामने वे कठिनाइयां नहीं थीं जो हमारे सामने हैं, वे प्रश्न नहीं थे जो हमारे सामने हैं। अक्सर जिन देशों का नाम लिया जाता है वे छोटे देश हैं और यहां की जनता डिमिग्लिन्ड है। हमने एक दूसरा रास्ता लिया है और जो रास्ता लिया है वह लोकन्त्र का रास्ता लिया है। अगर

### [श्रीमती इन्दिरा गांधी]

हम कुछ नहीं कर पाते तो आज हम सब एक साथ इस सदन में नहीं बैठ पाते और जो जी में आता नहीं कर सकते। यही एक बहुत बड़ी चीज इन 18 वर्षों में हुई और इस वक्त जब हम चारों तरफ दूसरे देशों को देखते हैं तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि वहां पर क्या-क्या हुआ है। अगर हम इस चीज को न भूलें तो अच्छा है।

जैसा कि मैंने कहा कि कमियां हुई हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी जारों के साथ कहना चाहती हूँ कि हमने जो करके दिखाया है वह किसी देश से कम नहीं है। अगर आप यह देखें कि जितना हमने किया है वह कितनी कठिनाइयों का सामना करके किया है। जब हम आजाद हुए थे तो दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं था जो यह समझता था कि हम उम आजादी को रख सकेंगे। सब समझते थे कि हमारी एकता नहीं रहेगी, लेकिन हमने अपनी बुनियाद बनाई और जब हमने कहा कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, तो उस समय दूसरे देशों में कितनी आवाज उठी थी कि एक अनपढ़ देश कैसे लोकतंत्र को समझ सकेगा। किस तरह से वह अपने चुनाव को ठीक तरह से कर सकेगा। लेकिन एक के बाद दूसरी बात हमने की और उसको पक्का किया। इस तरह से हम एक कदम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह नई बात है। जैसा मैंने कहा और मैं उसको फिर दोहराना चाहती हूँ कि जिस रफ्तार से हम जाना चाहते हैं उस रफ्तार से नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा भी कसूर है और शायद जो दूसरे दल हैं उनका भी कसूर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (उत्तर प्रदेश) :  
हमारा क्या कसूर है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कसूर यह है कि लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि जो विरोधी

दल होते हैं वे थोड़ा-सा सरकार का पांव काटने की कोशिश करते हैं। जो कार्य सरकार करना चाहती है उनमें अकसर उनसे विचार नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वे उस कार्य को सुस्त करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें लोकतंत्र में स्वाभाविक हैं और मैं नहीं कहती हूँ कि आप न करें, आप अपने रास्ते पर चलें। लेकिन यह समझते हुए चलें कि इन चीजों की रफ्तार तेज नहीं हो सकती है। पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक कार्यक्रम है जिसमें मुझे दिलचस्पी है और हमारे देश को भी है। वह है परिवार नियोजन का कार्यक्रम। क्योंकि प्रत्येक योजना के अंत में जैसा कि बताया जाता है कि हमारी आबादी 6 से 7 करोड़ तक बढ़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी मुश्किल है। इसके साथ ही साथ सब चीजों का उत्पादन बढ़ाना है और प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़ानी है। वह आय तो बढ़ेगी ही और मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वह रुकेगी, वह बढ़ेगी। लेकिन जितनी बढ़नी चाहिये, जितनी बढ़ाने की जरूरत है, उससे हम इस समय जनता को आराम नहीं पहुंचा सकते हैं। शायद मेरी बहिन श्रीमती परांजपे ने यह प्रश्न उठाया था।

जब दूसरा प्रश्न शिक्षा संस्थाओं की स्वतन्त्रता के बारे में है। श्री गोविन्दन नायर और श्री वाजपेयी जी ने इसके बारे में जिक्र किया था। मैं पूरे तौर से उनसे सहमत हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिये कि हमारी जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनका स्वतन्त्र रूप रहे और वे अपना रास्ता खुद ढूँढ़ें। सौभाग्य से शिक्षा मंत्री जी भी यही बात मानते हैं और वह कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यह बात हो।

शायद बहुत वर्ष हुए जब पंडित जी बाहर गये हुए थे तो उनसे पूछा गया था कि कौन-सा खास प्रश्न आपके सामने हिन्दुस्तान में है ? उन्होंने कहा कि मेरे सामने 40 करोड़ प्रश्न हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वह एक

प्रश्न है। अब वह संख्या इस वक्त बढ़ गई है। अब हमें यहां की जनता के लिए खाना, कपड़ा, काम, घर और शिक्षा, ये सब चीजें देनी हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न हैं उनमें से बहुतों का हल नहीं हो सकता है क्योंकि देश इतना बड़ा है कि वे छोटे प्रश्न भी बढ़े हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह से जिस प्रश्न को हल करना चाहिये उसको हल करने में देरी लगती है और मुष्किल भी पड़ती है।

अब एक बहुत जरूरी सवाल है और बाहर इस बारे में काफी राय है। यह एमरजेंसी का सवाल है। इस समय में उसके बारे में कुछ नई बात नहीं कह सकती हूँ। मैं आप सब लोगों के सामने पहले ही अपने विचार रख चुकी हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि जो हमारा विधान है, हमारे जनता के जो अधिकार हैं, वे किसी भी रूप से कट न जाएं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। मैंने पहले जैसे कहा था कि हम इस सारे मामले को फिर से और बहुत गहराई से, आप सबके विचारों को मद्दे नज़र रखते हुए सोचेंगे। जो यहां पर विचार रखे गये हैं, माननीय सदस्य श्री अकबर अली खान ने रखा, उन सबका भी ध्यान रखा जायेगा। नगर इस सिलसिले में मुझे एक बात कहनी है और वह यह है कि हमारी सीमा पर जो खतरा है वह कम नहीं हुआ है। खतरा अब भी है और आप सब माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1962 में जब चीन का हमला हुआ था तो उस समय कितना ऊघ्रम हुआ था कि क्यों नहीं हमारी सेना तैयार थी। तब हम यह जान नहीं सकते थे कि चीन का हमला उर्सा जगह पर होगा, नेफा पर होगा या लद्दाख पर होगा या किसी और जगह पर होगा, लेकिन सारे देश में ऊघ्रम हो गया। अब भी ऐसी समस्या है और हमको मालूम है कि चीनी सेनाएं वहां बंठी हैं, हम पर हमला कर चुकी हैं, एक दफा बहुत जोरों से और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा। तो यह होते हुए भी अगर हम इसको मूल

जायं तो आप ही लोग क्या कहेंगे यह आप अपने दिलों से पूछ सकते हैं।

एक और अहम मसला है। वह जो पंजाबी सूबे की मांग हुई उसके बारे में अभी यहां तो कुछ बहुत मैं नहीं कह सकती हूँ। आप माननीय सदस्यों ने शायद सुना होगा कि मैंने इस सिलसिले में एक पत्र संत फतेह सिंह जी को लिखा था और उनका जवाब कल मुझे मिला। उन्होंने अपना उपवास मुलतवी कर दिया है, चार हफ्ते के लिये, मुलतवी कर दिया है यानी मार्च के आखिर तक। हमारी कोशिश पहले भी रही है और अब भी रहेगी कि जो भी निश्चय हो, जो भी निर्णय हो, वह ऐसा हो कि जितने लोग उस जगह रहते हैं उनमें से अधिक से अधिक लोगों को सन्तोष मिले और सारे देश में कम-से-कम दूसरे नये प्रश्न पैदा हों। आप जानते हैं कि जब भी एक प्रश्न हल होता है—लोगों के व्यक्तिगत जीवन में होता है और राष्ट्रीय जीवन में भी होता है—तो बहुत-से नये प्रश्न हमेशा उठ खड़े होते हैं। इसलिये कोई भी हम रास्ता ढूँढ़ें तो यह देखना है कि नये प्रश्न जो हों वे किस तरह के होंगे और वे कहीं इससे अधिक परेशानी में देश को न डालें।

विदेश नीति के बारे में श्री अण्णादुरै जी ने जिक्र किया था। हमारी नीति वही है जो पहले थी। इसलिये नहीं है कि पहले से चली आ रही है, और हम इस रास्ते में हैं, कैसे इससे निकलें, यह मेरा तरीका नहीं है। जो नीति हम मानेंगे, जिस मार्ग पर चलेंगे, उस रास्ते पर चलने का एक ही कारण है और वह यह कि आज की समस्या में हम उसको ठीक मानते हैं अपने अनुभव से और जो आज की समस्या की जानकारी है उसको देखते हुये। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि जो नीति हमारे नेताओं ने पहले चलाई थी वह आज हमारे लिये ठीक नीति है और खाली यह हम ही नहीं मानते हैं बल्कि एक-एक करके करीब-करीब सभी देश दुनिया के उसको मानने पर आ गये हैं यूरोप में भी, एशिया में भी और अफ्रीका में भी।



[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

ताशकन्द का जिफ्र वाजपेयी जी ने, सरला बहन जी ने और और लोगों ने किया। उस पर भी मैं कोई नई बात नहीं कह सकती हूँ। यहाँ पर उस पर चर्चा हुई और सबके दृष्टिकोण माननीय सदस्यों को मालूम हैं। ताशकन्द घोषणा में कोई नई बात नहीं थी लेकिन जो कुछ पुरानी बात थी, जो यूनाइटेड नेशन्स के चार्टर में थी, वही एक नये तरह से, ताजे तरह से, फिर से हमारे सामने रखी गई और एक नया मौका हमें मिला। लड़ाई के बाद जब इतना दोनों तरफ गुस्सा, रंज और ऐसी बहुत-सी भावना उत्पन्न हुई थी तो एक नया मौका मिला कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ समझौता करें और शांति से रहने का प्रयत्न करें। जो भी उसमें था, हमारे सैनिकों को कई जगहों से वापस लेना और कई ऐसी बातें थी जो पूरी हो रही हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हों जो हमारे लिये पूरे तौर से लाभदायक नहीं थीं, लेकिन जब किसी से भी समझौता करना हो तो लेन-देन कुछ न कुछ होना चाहिये। आप सबों ने देखा होगा समाचारपत्रों में कि पाकिस्तान में भी इस घोषणा का काफी विरोध हुआ। बहुत से लोग वहाँ पर हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा समझौता हो। हमारा कर्त्तव्य यह है, हमारी चेष्टा यह होनी चाहिये कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि शांति हो। इसलिये नहीं कि खाली शांति एक अच्छी चीज है, एक अच्छा आदर्श है, लेकिन इसलिये कि बिना शांति के हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते। हमारा देश मजबूत नहीं बने तो फिर हम किसी दूसरे देश का सामना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिये हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि शास्त्री जी ने जिस घोषणा पर दस्ताखत किये उसको हम हर एक तरह से पूरा करने की कोशिश करें। सारी दुनिया ने इस घोषणा का स्वागत किया। केवल चीन ने नहीं किया। चीन का रवैया भी आप जानते हैं। जो हमारी दूसरी नीतियाँ हैं उनके भी वे विरोधी हैं। हमारी

सीमा पर वे भयंकर रूप से दटे हैं, लेकिन हमारी जो चीन से असल लड़ाई है वह खाली सीमा की लड़ाई नहीं है। सीमा की भी है, लेकिन विचारधारा की भी लड़ाई है। चीन नहीं चाहता कि भारत की जो नीतियाँ हैं, भारत की जो विचारधारा है, उनका असर दूसरे देशों पर पड़े। जो-जो बातें चीन ने कीं हमारे देश में और दूसरे देशों में जो कोशिशें कीं उनका एक ही ध्येय था कि किसी न किसी तरह से उसका जोर बढ़े और भारत कमजोर पड़े। यह एक और कारण है और हमें देखना है कि हम अपने देश की मजबूती में किसी तरह की सुस्ती न दिखायें।

दूसरी बात यह है कि बियतनाम बहुत संभ्रम स्थिति में है जिसको हम सब स्वीकार करते हैं और हम समझते हैं कि जितनी जल्दी वहाँ सुलह हो सके उतना ही दुनिया के लिये और हमारे लिये भी अच्छा होगा। हम समझते हैं कि जेनेवा संधि के अन्तर्गत अगर यह हो सके तो वह सबसे अच्छा तरीका होगा। हमारी यह खास जिम्मेदारी है क्योंकि हम कमोशन आफ कंट्रोल एंड सुपरविजन के अध्यक्ष हैं।

रोडेशिया की हालत भी आप जानते हैं और आप यह जानते हैं कि हमारी सहानुभूति वहाँ पर किस तरफ है। वहाँ के जो गरीब अफ्रीकी लोग हैं, जिनका वह देश है, उनकी तरफ हमारी सहानुभूति है। यह जिम्मेदारी तो असल में इंगलिस्तान की है, लेकिन हम जो भी कर सकते हैं वह हम करने को तैयार हैं।

जम्बिया हमारा एक दोस्त देश है रोडेशिया के पास और जो रोडेशिया में हो रहा है उसकी वजह से वहाँ बहुत कठिनाई हो रही है। यहाँ पर कल ही माननीय सदस्यों ने सुना कि किस तरह की मदद हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं।

दक्षिणी अफ्रीका के बारे में भी हमें काफी परेशानी है और हम मानते हैं कि जो प्रतिबन्ध उस पर डाले गये हैं वे सब देश अगर मानें तो शायद वहाँ कुछ हालत थोड़ी बदल सकती थी। वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला, बहुत वर्ष

हो गये, उसको सन् 1941 में, लेकिन जो मैंने देखा वहाँ उससे काफी हैरानी मुझे हुई। मैंने यह भी देखा कि लोगों को कितनी जल्दी सब तरह की बंदियों की आदत हो जाती है। अगर वे वैसे देश में रहें, जहाँ ऐसी बंदियों हों।

वहाँ श्री अण्णादुरै ने और शायद और लोगों ने पूछा कि हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय बहुत साफ है। उसको आप किसी भी नाम से पुकारें, वह ध्येय बदलता नहीं। हम उसको समाजवाद कह सकते हैं। कोई नया नाम उसके लिये सोचें, खास हिन्दुस्तानी नाम, खास भारतीय नाम कोई समझें, तो वह नाम भी दे सकते हैं। लेकिन ध्येय यह है कि बहुत गरीब देश हमारा है, सदियों से गरीब रहा है, यह आजकल में गरीब नहीं हुआ है, तो किस तरह से इस देश में हम एकता ला के, स्थिरता ला के, इसकी गरीब जनता को ऊपर उठायें। उनको शिक्षा मिले और जो जरूरत की चीजें हैं, उनका बराबरी से बंटवारा हो, बराबरी का मौका हो। यह हमें देखना है कि कैसे हम इसे जल्दी से जल्दी अपने देश में कर सकें। मैं मानती हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि जब हाल के संघर्ष में सारा देश एक हो सका, तो हम इस चीज में भी—बहुत बड़ा संघर्ष यह भी है, किसी एक संस्था की बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है, सारे देश की बात है—क्यों नहीं एक हो सकते हैं। हम जोरों से उसमें सहयोग करें, जिससे अपने देश को सुधार सकें और उसे उस ओर आगे ले जा सकें, जिसके लिए हमारे नेताओं ने स्वप्न देखे थे और जिनके हमने भी सपने लिये हैं।

मैंने उन गदन में भी कहा और यहाँ भी दोहराती हूँ कि जितने आप बुजुर्ग लोग हैं, आपका अनुभव है, मुझे आशा है उस अनुभव का फायदा मैं उठा सकूंगी और आप पूरा सहयोग मुझे देंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि युवक समाज का सहयोग भी

मैं ले सकूँ—खाली इसलिए नहीं कि छोटी उम्र के लोग हैं, लेकिन इसलिए कि—आज हिन्दुस्तान में हम सबको शिक्षा नहीं दे सके, बहुत कम लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर सके—जो लोग शिक्षा प्राप्त कर सके हैं, उनमें से एक काफी बड़ी संख्या है, जो मुझे इस बात का बहुत गौरव है, अपने-अपने कामों में बहुत ऊँचे गए हैं और जिन्होंने अपने लिए, चाहे विज्ञान हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हों, जगहें बनाई हैं। उनकी दूसरे देशों में बहुत मांग है। हम चाहते हैं कि उनका जो ज्ञान है और जो शक्ति है, उसे अपने देश में काम में लाएं और वे भी इस देश को आगे ले जाने में हाथ बंटाएं। हम जो राजनीति में हैं, लक्ष्य तय करते हैं लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, उसका काम रास्ता ढूँढ़ना होता है कि किस तरह से इन कामों को पूरा करें। इस तरह से हम मिल कर इन कामों को उठाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि—और भारत की जनता में मुझे पूरा विश्वास है—आज जो कठिन समस्याएं हमारे सामने हैं, उनका हम सामना कर सकते हैं और इन कठिन दिनों से पार होकर एक नया भारत बना सकते हैं।

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : Mr. Chairman, while congratulating the Prime Minister for the lucid clarification of the various points raised in this House, since she mentioned the question of Punjabi Suba, I would like to seek one clarification, which is agitating the mind\* of many of the Members of Parliament and that is about the status and scope of the Committee of Members of both Houses of Parliament appointed to advise the Cabinet Sub-Committee on the question of Punjabi Suba. The question was raised in the other House yesterday and doubt-were raised whether it could be a Parliamentary Committee. There are quite a number of constitutional points involved as to whether it is a Parliamentary Committee or not and I would, therefore, seek through you, Sir, a clarification from the worthy Prime Minister on this point.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I have a suggestion. I think that it is a delicate matter and it would be better for

[Shri Bhupesh Gupta] the Prime Minister to invite the leaders of the Opposition and the Congress Party to discuss the question of Punjabi Suba.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: It is a good idea and I accept it

SHRI BHUPESH GUPTA: What » it ?

MR. CHAIRMAN : She says it is a good idea and she will do that.

**श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) :**  
श्रीमान्, मुख्य मंत्री महोदया ने . . . . .

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मंत्री ।**

**श्री अर्जुन अरोड़ा :** हम यू० पी० के रहने वाले मुख्य मंत्री महोदया के जादी हो गए हैं। प्रधान मंत्री महोदया ने वियतनाम में शांति की अभिलाषा प्रगट की है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार वियतनाम में शांति लाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और दोनों पक्षों को नजदीक लाने के लिए कुछ इनीशिएटिव निकट भविष्य में लेगी ?

MR. CHAIRMAN : I think it is enough I have to put the amendments to vote. Amendment No. 1, Mr. D. L. Sen Gupta is not here. I will put it to vote.

The question is :

1. That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that white touching upon the various problems confronting the country, the Address says nothing to inspire anybody, particularly the starving common man and the exploited masses'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : Amendment Nos. 2 ' Shri Chordia.

**श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) :** उन्होंने जो मापण किया उसमें ये सब बातें आई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रेस किए जाएं और सदन इनको स्वीकार करे।

MR CHAIRMAN : The question is :

2. That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the political injustices perpetrated under the cover of the state of emergency and does not assure that they would not be repeated in future'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :—

3. 'That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the economic distress all over India'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

4. "That at the end of the motion the following be added, namely.—

'but regret that the Address fails to take note of the inflation of the currency and the consequent dearness and the said state of affairs arising therefrom'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

5. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the problem of increasing unemployment among the educated and does not indicate steps for the solution thereof'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

6. 'That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the sad plight of the goldsmiths caused by the gold control nor indicate measures for relieving them from their plight'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

7. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not indicate steps for the abrogation of

article 370 of the Constitution regarding Kashmir.' "

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

8. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not caution the people in regard to the influence being exercised by the U.S.S.R. in the question of Kashmir'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is

9. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the pitiable plight of the Harijans and the members of the Scheduled Tribes, nor indicate measures to give relief to them'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is

10. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the failure of the Government of India in regard to—

- (a) eradication of corruption
- (b) removal of unemployment
- (c) ending inflation of currency;
- (d) checking rising prices;
- (e) solving the food crisis;
- (f) reducing administrative expenditure;
- (g) solution of the power crisis;
- (h) solution of the water crisis'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is

11. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not refer to sacred resolve of liberating parts of the territory of India which are under the unlawful occupation of Pakistan and China and the measures for liberating them.' "

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is

12. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to indicate the measures to be taken to raise the standard of living of the common man'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

13. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to take note of the necessity of establishing diplomatic relations by India with Israel'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

14. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to take note of kidnapping of people by Naga hostiles and to indicate the measures for checking the recurrence of such incidents in future.'"

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

15. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not show any awareness of the growing lack of restraint, immorality and corruption in the society and does not indicate the measures for removing them'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

16. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to give any inspiration to the people to follow the eternal and truthful principles in order to reform the society'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is :

17. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not call upon the countrymen to make India militarily strong and to prepare the people to face any future crisis.' "

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

18. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to indicate measures for channelling the feelings of patriotism aroused by the Pakistani aggression and for promoting the interest of the nation while maintaining the unity of the country-merr'

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

19. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to take note of the increasing burden of indebtedness upon the farmers and their worsened economic condition'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

20. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not indicate the measures for relieving the farmers of their indebtedness and for ameliorating their economic condition'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

21. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to take note of the ever increasing poverty and unemployment amongst the oilmen, the cobblers, the ironsmiths, the potters, the finsmiths etc., in the rural areas and does not indicate the measures to remove the same'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

22. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not make proper mention of the unsatisfactory state of foreign trade and does not indicate the measures to improve the same'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

23. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to take note of the problems of forced immigration of Indians from abroad to India, of permission not being given to them to bring their property to India, and of the failure of the Government to rehabilitate them in India'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question

24. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not make mention of the encouragement to be given to Hindi, the national language of India'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

25. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to give any concrete suggestions in respect of making the country self-sufficient in foodgrains'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

26. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the deplorable tendency of Government to make India indebted'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

27. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not make mention of the important problem of setting up of new industries in the industrially backward areas of Madhya Pradesh'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

28. "That at the end of the motion the following be added, namely :

"but regret that the Address does not take note of the fact that due to want of equipment Madhya Pradesh is not able to utilise its power generating capacity and the power generated by it nor does the Address promise to meet that shortage'."

*The motion was negatived.*

Mr. CHAIRMAN : The question is :

29. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not lay emphasis on setting-up of new iron works in Madhya Pradesh for utilising its iron-ore resources."

*The motion was negatived.*

Ma. CHAIRMAN : The question is :

30. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"\*but regret that the Address, while making reference to the friendly ties with our neighbours having been strengthened, does not take note of the fact that the people of Indian origin are not being treated properly in the neighbouring countries, that they are being compelled to flee those countries, and that no compensation is being paid for their properties."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

31. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address merely refers to the peaceful methods for resolving the conflict in Vietnam instead of giving priority to the just methods for resolving the conflict."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

32. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address takes note only of the figures of the growth

of national income without at the same time giving statistics with regard to dearness also."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

33. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address while making a reference to statutory rationing does not take note of the food crisis being faced by the people in different parts of the country and does not indicate the solution for resolving this crisis."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

34. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address, while making a reference to other measures to increase the production of foodgrains, fails to make a special reference to the fundamental factor in this regard, namely, the irrigation facilities without which all other measures yield no result'."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

35. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address while making a reference to the education of the children of the primary schools does not take note of the fact that at many places there are insufficient arrangements for accommodation for the children of the primary schools, playing grounds and other similar amenities."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

36. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to take note of the fact that during the last year the Chinese have been regularly committing aggression against India and does not indicate the measures to prevent such aggression."

*The motion was negatived.*

Ma. CHAIRMAN : The question is :

37. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not make any reference to the liberation of Pakhtoonistan and Tibet.'"

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

40. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not give any indication of an intention immediately to end the state of emergency declared by the President and to restore the normal functioning of full democratic liberties in the country.'"

*The motion was negatived.*

MB. CHMRMAN : The question is :

41. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to suggest a complete reorientation of the Government's policies to deal with the serious economic situation and the distress caused by its faulty food policies, and concrete measures to put agriculture on its feet so as to end the present over dependence on imported foodgrains, such as—

- (i) abolishing zonal and local restrictions on the sale and movement of foodgrains, gur, groundnut and all edible oils and the re-establishment of a common market throughout India;
- <ii) giving the highest priority in all plans and allocations for water, credit, roads and providing incentives and facilities to farmers through the availability of fertiliser, good seed, electric power, implements, diesel and kerosene oil at reasonable prices;
- (iii) putting an end to compulsory procurement and accepting the right of the farmer to sell his grain in the free market without any maximum price being imposed;

(iv) working out a price support policy under which the Government would, along-side of the traders, be an unlimited buyer of foodgrains from producers at remunerative prices to be determined according to clearly stated principles enunciated by an Agricultural Price Commission functioning as an independent statutory body; and

(v) as a temporary measure, until production catches up with demand, supplying the poorer sections of the population with subsidised foodgrains purchased by the Government from the big farmers at remunerative prices."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is ;

42. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to admit the Union Government's responsibility for the current debacle in the provision of adequate food supplies to the people of Kerala, and to mention the existence of scarcity conditions in Orissa.'"

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

43. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not show any recognition of the fact that the defence of South Vietnam and of Malaysia against aggression is in India's vital national interests, nor any readiness to take the initiative in building up a system of regional co-operation and security among the countries that lie between India, Japan and Australia to meet the threat of Chinese Communist expansionism.'"

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is ;

44. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not indicate any readiness to follow up

the implementation of the Tashkent Agreement by building an economic base for friendship between India and Pakistan by the abolition of tariffs and duties on goods crossing the frontier between the two countries and by setting up a Joint Committee to consider ways and means by which economic and other forms of co-operation between the two countries may be furthered to the mutual benefit of both."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : Amendments Nos. 60 to 69, Shri Bhupesh Gupta. Do you press them ?

SHRI BHUPESH GUPTA : It is difficult to say...

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : He wants to make a speech.

SHRI BHUPESH GUPTA : I do not want to make a speech. Most of them relate to the question of emergency. I have a feeling— I should be contradicted if I am wrong— that the Prime Minister is thinking of withdrawing the emergency. I have a feeling . . . .

MR. CHAIRMAN : She has said what she has said. You can draw your inference.

SHRI BHUPESH GUPTA : Therefore, at least one amendment I withdraw as a gesture.

MR. CHAIRMAN : Which one ?

SHRI BHUPESH GUPTA : One of the emergency amendments, whichever you like.

PROF. M. B. LAL (Uttar Pradesh) : This cannot be left to the Chair.

SHRI BHUPESH GUPTA : The first amendment that appears on the list.

MR. CHAIRMAN : It is amendment No. 60. Has he the permission of the House to withdraw ?

HON. MEMBERS : Yes.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I beg leave to withdraw my amendment.

*\*Amendment No. 60 was, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN : I shall put amendments Nos. 61 to 69 to vote. The question is :

61. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not take notice of the fact that the emergency and the powers under it, including in particular the Defence of India Rule\*, are being used by Government and the ruling party for suppression of popular movements, for intimidating and persecuting the political opponents of the ruling party and keeping alive an atmosphere of fear."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

62. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the serious observations made by the Supreme Court as well as many High Courts in the country regarding emergency and the use of the Defence of India Rules."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

63. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not take any notice of the fact that well over a thousand leaders and workers of different political parties including Members of Parliament and State Legislatures are still held in detention without trial under the Defence of India Rules."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

64. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not take note of the fact that whereas the ruling party in the country has already started its preparations for the fourth general elections, the Opposition parties are handicapped in many ways by the

\*For text of amendment, *vide* col.—916 *supra*.



continuance of the emergency and the Defence of India Rules making their preparatioai for the elections difficult.' "

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

65. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the fact that there cannot be any fre<sup>^</sup> and fair elections at all unless the state of emergency is withdrawn and the Damocles' sword which is a constant intimidation and threat to the masses is removed."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

66. That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address does not take note of the fact that the continuance of the emergency and the Defence of India Rules have been condemned by eminent jurists in the country as tending to give rise to constitutional dictatorship."

*This motion was negatived.*

Mn. CHAIRMAN : The question is :

67. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to uannounce the immediate end of the state of emergency and the release of all political detenus."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

68. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to condemn the resumption of bombing of the Democratic Republic of Vietnam and the continued violation of the Geneva Agreement and the escalation of hostilities by the U.S.A., endangering world peace and particularly peace in South East Asia.' "

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is .

69. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'but regret that the Address fails to recognise the dismal failure of the food and agriculture policy of Government leading to starvation, high prices, widespread distress and dangerous dependence on imports; and also fails to spell out the necessary steps for self-sufficiency in food and national control over the wholesale trade and distribution of foodgrains."

*The motion was negatived.*

MR. CHAIRMAN : Now, the amendments have been disposed of, I shall now put the motion to vote.

The question is :

"That an Address be presented to the President in the following terms :—

'That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament assembled together on the 14th February, 1966."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at halfpast two of the Clock, the DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

#### **REQUEST FOR A STATEMENT ON COMMITTEE ON PUNJABI SUBA**

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : Madam, before you call upon Mr. Vajpayee to move his motion, I would like to invite the attention of the House to the matter which I raised in the morning and which was not replied to because of the intervention of Shri Bbupesh Gupta. I would request the Government through you, Madam, that *the* Home Minister

should come and make a statement clarifying the position about the status and scope of this Committee on Punjabi Suba.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Prime Minister took the suggestion of the hon. Member. I think the Prime Minister replied.

SHRI M. P. BHARGAVA : The Prime Minister did not reply.

THE DEPUTY CHAIRMAN : But a suggestion was made that it need not be discussed.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I have no objection to the Home Minister coming.

THE DEPUTY CHAIRMAN : That was replied to in the sense that it was not necessary to raise the issue in this House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Uttar Pradesh) : Madam, the question of whether the Committee on Punjabi Suba is a Parliamentary Committee or not cannot be decided at a meeting of leaders, of different parties. It is for the Chair, for you and for the House to decide. I feel there is no relevance in the suggestion made by Mr. Bhupesh Gupta which was accepted.

SHRI BHUPESH GUPTA : I am jealous of Parliament's privileges and rights just as many matters are raised and brought here.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If that is the opinion of Members, let this be conveyed to the Government.

Mr. Vajpayee, you may move your motion.

#### MOTION RE FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जायें।”

\*[“That the food situation in the country be taken into consideration.”]

महोदया, खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में सरकार ने जो समीक्षा प्रकाशित की है उससे

\*[ ] English translation.

M21RS/66—4

यह ज्ञात होता है कि खाद्य स्थिति अत्यंत गम्भीर है। अवर्षण के कारण अनेक राज्यों में फसल को गहरी क्षति पहुँची है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग इस अवर्षण से सर्वाधिक प्रभावित हैं। संकट की गम्भीरता का अनुमान इस बात से भी लग सकता है कि इस समय 20 लाख व्यक्ति भिन्न-भिन्न राज्यों में राहत के कार्य पर लगे हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार मार्च के महीने में यह संख्या 50 लाख तक हो जायेगी।

प्रश्न यह है कि देश में कितने अनाज की कमी है, क्या सरकार उसका कोई ठीक अनुमान लगा सकती है। कुछ क्षेत्रों में यह शिकायत की जाती है कि खाद्य मंत्री महोदय अनाज की कमी के अनुमान निरंतर बढ़ाते रहे हैं। समीक्षा के अनुसार कमी के आंकड़े 140 से 150 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच सकते हैं। प्रश्न होता है कि क्या यह आंकड़े ठीक हैं। सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आंकड़े एकत्र करने की सरकारी प्रणाली दोषपूर्ण है। यह भी कहा जाता है कि परिस्थिति को जितना गम्भीर बता कर पेश किया जाता है उतनी गम्भीर परिस्थिति नहीं है। पूछा जाता है कि अगर देश में सचमुच में अनाज की कमी है तो यह क्या कारण है कि कमी वाले क्षेत्रों में भी काले बाजार में अधिक दाम दे कर जितना अनाज प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं।

महोदया, शायद सरकार भी इस प्रश्न पर एकमत नहीं है कि देश में कितने अनाज की कमी है। आज के ही समाचार-पत्रों में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लन्दन के सन्ध्याकालीन पत्र “स्टैंडर्ड” को जो भेंट दी है उसका विवरण छपा हुआ है। प्रधान मंत्री महोदया का कहना है, मैं उन्हीं शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ : “भारत में अन्न की कमी उतनी अधिक नहीं है जितनी कमी उसके अच्छे ढंग से वितरण की है। फिलहाल देश में अनाज का समान वितरण नहीं हो पा रहा है।” उन्होंने यह भी कहा है कि “देश में अनाज की

**[श्री अन्न बिहारी वाजपेयी]**

कमी है लेकिन भुखमरी की हालत नहीं है। अनाज की कमी का खास वहुत ही बड़ा-चड़ा कर खाँचा गया है। सरकार जिस तरह से भिन्न-भिन्न देशों से वहाँ की सरकारों से, गैर-सरकारी संस्थाओं से, अनाज या दूध का पाउडर या अन्य उपयोग की वस्तुयें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है उससे तो यह पता लगता है कि परिस्थिति भयावह है। स्पष्टतः इस बात के पक्के अनुमान लगाये जाने चाहिए कि सबभूव में कमी कितनी है और फिर सोचा जाए उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है।

महोदया, एक बात साफ है कि अन्न की कमी के सवाल को कानून या व्यवस्था का सवाल बना कर हल नहीं किया जा सकता। केरल में जो कुछ हुआ था पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है या अन्य प्रांतों में जो कुछ हो सकता है उसने एक बात साफ है कि यदि राज्य सरकारें लाठी या गोली से जनता के असंतोष को दबाने का प्रयत्न करेंगी तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। देश में अनाज की कमी है, वितरण ठीक न होने के कारण कमी का प्रभाव और भी बढ़ गया है, लोगों में असंतोष है, अन्य प्रश्नों पर जो असंतोष है वह भी अपने निकलने के लिये मार्ग खोजता है, और अन्न की कमी लोगों के सामने आ जाती है और जब राज्य सरकारें दमन के तरीके अपनाती हैं तो समस्या सुनझने के बजाय और उलझ जाती है।

केरल की जनता को इस बात पर रोष होना स्वाभाविक था कि उसे मद्रास और आंध्र की तुलना में राशन में चावल की मात्रा कम दी जा रही है। वहाँ के भूतपूर्व राज्यपाल महोदय ने भी लोगों को केन्द्र के विरुद्ध उकसाया। यह बात अलग है कि जब लोग भड़क गये तो उन्होंने दमन की धमकी दी जिससे परिस्थिति और भी बिगड़ी।

अमी-अमी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है बड़ा खेदजनक है। बगीरहाट में 16 तारीख को लोग एक स्मृतिपत्र पेश करने के लिये

अधिकारियों के पास जा रहे थे। यदि कोई अधिकारी स्मृतिपत्र ले लेता और सहानुभूति के साथ जनता की मांगों पर विचार करने का आश्वासन देता तो शायद परिस्थिति न बिगड़ती। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वहाँ जनता का स्मरण-पत्र लेने के लिये भी कोई अधिकारी नहीं था। राज्य सरकारें किस तरह से काम करती हैं यह इसका एक उदाहरण है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले तीन महीने से उन क्षेत्रों में चावल की कमी है। यह बात नहीं है कि चावल सरकारी गोदाम में नहीं है। लेकिन जो चावल सरकारी गोदाम में है वह जनता में वितरण के लिये नहीं लाया गया। चावल की कमी के साथ मिट्टी के तेल की कमी भी मिल गई। लोगों का उत्तेजित होना स्वाभाविक था, लेकिन अपर अधिकारी कुशलता से परिस्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न करते तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न होती। लेकिन लोगों की आवाज को दवाने के लिये वहाँ गोली चली और बगीरहाट में हुए गोलीकांड के विरोधस्वरूप दूसरे दिन स्वरूपनगर में विद्यार्थियों ने जलूस निकाला। वहाँ भी गोली चली और दस वर्ष का एक लड़का पुलिस की गोली का शिकार हो गया। उसका नाम था नूरुल इस्लाम। उसे स्कूल के मैदान में दफनाया गया तो स्कूल के ड्रैडमास्टर ने आँखों में आंसू भर कर कहा कि इस लड़के की कब्र पर हम एक "एपिटॉफ" लिखेंगे कि "यहाँ सोया हुआ है नूरुल इस्लाम जिसने मांगा था चावल और जिनको मिली गोली।" बड़ा दर्दनाक प्रसंग है यह। खाद्य मंत्री महोदय राज्य सरकारों को यह बात अच्छी तरह से समझाएं कि जब देश में अन्न का अभाव है और शासन सबको उचित मात्रा में पर्याप्त अनाज देने की स्थिति में नहीं है तो लोग अगर उत्तेजित होते हैं तो जरा कुशलता से, समझदारी से, काम लें। मेरा स्पष्ट मत है कि जब तक किन्ती अधिकारी के या पुलिस वाले के मारे जाने का खतरा न हो तब तक गोली नहीं चलनी चाहिये। थोड़े से पत्थर फेंके जायें और पुलिस गोली चला दे और गोली चलाने

का आदेश देने के लिये मैजिस्ट्रेट भी न हो, न्यायाधीश भी न हो तो फिर लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन होगा। हमें परिस्थिति का मुकाबला बड़ी सहानुभूति के साथ करने का यत्न करना चाहिये।

इस समय मुख्य समस्या अनाज के वितरण की है। देश में जितना अनाज प्राप्त है, जितना हम विदेशों से ला रहे हैं, क्या उसे ठीक तरह से बांटा जा रहा है? जब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान क्षेत्रीय प्रतिबंधों की ओर जाता है। जोनल रेस्ट्रिक्शन्स रहे या हट जायें, यह एक विवाद का विषय बन गया है। मैंने 21 फरवरी को एक सवाल किया था कि क्या सरकार जोन समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, तो मुझे जो उत्तर दिया गया वह इस प्रकार है :

इसके बाद खाद्य मंत्री महोदय ने लोक सभा में बताया कि उन्होंने विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है जो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देने वाली है। मैं जानना चाहूंगा, इसमें कौन-कौन से विशेषज्ञ हैं? क्या विशेषज्ञ खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से संबंधित हैं या कुछ स्वतंत्रवेत्ता विशेषज्ञों के हाथ में यह सवाल सौंपा गया है। महोदय, मुझे आप क्षमा करें, विशेषज्ञ हमें हर तरह को राय देने वाले मिल सकते हैं। जैसे किसी मामले को लड़ने के लिये हर तरह के वकील मिल सकते हैं उसी तरह से किसी पक्ष को पुष्ट करने के लिये विशेषज्ञों की सम्मति ली जा सकती है। अगर विशेषज्ञ मंत्रालय से संबंधित हैं तो वे मंत्री महोदय का रुख देखकर रिपोर्ट देंगे, और मंत्री महोदय का रुख स्पष्ट है। वे क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं हैं।

"The necessity or otherwise of continuing the existing food zones is reviewed periodically in consultation with the Chief Ministers of the States. The date for the next review has not yet been fixed. It is, therefore, not possible to indicate at present when a final decision in the matter is likely to be taken."

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) : Then they are not experts.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा अनुरोध है कि खाद्यान्न से संबंधित किसी भी प्रश्न पर हमें आइडियालाजी के आधार पर विचार नहीं करना चाहिये फिर वह आइडियालाजी वह विचारधारा चाहे सोशलिज्म की हो या मुक्त व्यापार की, लेसेज फेरी—*Laissezfaire*—की, स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा हो। हम यदि विचारधारा के पूर्वग्रह से मुक्त होकर, यथार्थवादी दृष्टिकोण से, खाद्यान्न के प्रश्न पर विचार करेंगे तभी हम आज की परिस्थिति में उसे हल कर सकेंगे।

कभी-कभी कहा जाता है कि हमने देश में समाजवादी समाज रचना का संकल्प किया है, अब हम अनाज का व्यापार व्यक्तिगत हाथों में कैसे छोड़ सकते हैं। मेरी दृष्टि से यह सोचने का तरीका ठीक नहीं है। जापान में समाजवाद नहीं है मगर सरकार अनाज का राजकीय व्यापार कर रही है और सफलतापूर्वक कर रही है। प्रश्न किसी सिद्धांत का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि आज की परिस्थिति में व्यावहारिक क्या है। मंत्री महोदय क्षेत्रीय प्रतिबंधों का इस आधार पर समर्थन करते रहे हैं कि इससे अच्छा कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण जो बुराइयां पैदा हो रही हैं उन पर भी हमको गौर करना होगा। हमारे यहां दो तरह के राज्य बन गए हैं एक बचत वाले राज्य हैं, एक कमी वाले राज्य। दोनों के बीच में एक दीवार सी खड़ी हो रही है। बचत वाले राज्य कमी वाले राज्यों को अनाज देने के लिये तैयार नहीं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने साफ कह दिया कि हम अपना अनाज बाहर नहीं जाने देंगे। आंध्र से, मद्रास से केरल में चावल भेजने में एक कठिनाई अनुभव हुई। यह ठीक है कि खाद्य मंत्री सभी मुख्य मंत्रियों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न करते हैं। मगर मेरा निवेदन है, बचत वाले राज्यों में अपनी फसल अपने तक सीमित रखने की जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है यह बड़ी घातक है। आज तो सभी राज्यों में

एक ही पार्टी का शासन है, कल अगर भिन्नभिन्न राज्यों में अलग-अलग दलों का शासन हुआ तो इस समस्या पर कैसे पार पाया जायेगा। मंत्री महोदय यह कह कर मुझे चुप करा सकते हैं कि निकट भविष्य में अन्य राज्यों में अन्य दलों की सरकारें बनने की कोई आशंका नहीं है। लेकिन दूरदर्शिता की मांग है कि हम समस्या के इस पहलू पर भी विचार करें। क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम अभाव पैदा होता है, मूल्यों में असाधारण वृद्धि होती है और उपभोक्ता गहरी कठिनाई में फस जाता है। इसके विपरीत क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण बचत वाले राज्यों में किसान को उसके परिश्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता और वह गेहूं, चावल की बजाय व्यावसायिक फसलों बोने की ओर आकृष्ट होता है।

महोदय, मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किये हैं जिससे पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में गन्ना, जूट, तम्बाकू, इनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। नेहरू जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश में गन्ने और गल्ले में होड़ लगी है। ऐसा लगता है कि इस होड़ में गन्ना जीत गया है, गल्ला पिछड़ गया है। 1950-51 में गन्ना 42.17 लाख एकड़ में बोया जाता था और 1961-62 में यह क्षेत्रफल बढ़कर 59 लाख 45 हजार हो गया। तम्बाकू का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। सन् 1950-51 में 1 करोड़ 11 लाख 6 हजार एकड़ भूमि में तम्बाकू बोया जाता था, जो बढ़कर 1 करोड़ 58 लाख 40 हजार एकड़ हो गया है। जूट में 14 लाख 11 हजार से बढ़कर 25 लाख 59 हजार एकड़ क्षेत्रफल हो गया है। पंजाब के किसानों को विशेषकर बड़े किसानों को जो अनाज रखने की क्षमता रखते हैं, इस समय शिकायत है कि उन्हें क्षेत्रीय प्रतिबंध के कारण अपनी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। यह ठीक है कि अगर प्रतिबंध हटा दिये जायें तो व्यापारी मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे, मैं इस तथ्य की ओर से आंख मूंदना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज, सरकार को तय करना है

कि बचत वाले क्षेत्रों में जिस अनाज के सड़ने और जिस अनाज में धुन लगने की आशंका है, उसे कमी वाले क्षेत्रों में जाने दिया जायेगा या नहीं? यदि व्यापारी थोड़ा मुनाफा कमाते हैं तो कड़वी गोली की तरह से उसे निगलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे पास आंकड़े हैं, उनसे पता लगता है कि पंजाब में इस समय 15 लाख मन गेहूं, 40 लाख टन चना, 25 लाख मन मक्का और बाजरा बाजार में पड़ा हुआ है और बाहर जाने के रास्ते बंद हैं। जिन दामों पर सरकार खरीदना चाहती है उस दाम पर लोग बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। नतीजा यह हो रहा है कि यह अनाज विगड़ रहा है। महोदय, मुझे आज सबरे कुछ चने दिये गये, ये चने पास हैं और मैं उन्हें टेबल पर नहीं रख सकता। इन चनों में धुन लगा हुआ है। बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ है। अब इस चने का क्या होगा?

यही स्थिति अन्य राज्यों में भी है। राजस्थान में भी चने की समस्या है। वहां पर 50 लाख मन चना, 10 लाख मन मक्का, 5 लाख मन जुआर पड़ी हुई है और उसे बाहर भेजने की छूट नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 लाख मन चना पड़ा हुआ है। जब चने की नई फसल आने वाली है। गेहूं की भी नई फसल आयेगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो नई फसल आने वाली है, उसको ध्यान में रख कर आप इस प्रश्न पर विचार करें कि अनाज के लाने ले जाने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, अन्तर्प्रन्तीय और अन्तर्राज्यीय प्रतिबंध उन प्रतिबंधों को हटाया जाय तो क्या बुराई होगी?

हम यह दावा करते हैं कि हमारा देश एक है। आज प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि देश में अगर कमी है तो मिलकर उसे बांटना चाहिये। बांटने से दुःख कम होता है और बांटने से सुख बढ़ता है। लेकिन उचित बटवारे की शर्त यह है कि हम देश के सभी भागों में अनाज के एक मूल्य निर्धारित करने का प्रयत्न करें लेकिन क्षेत्रीय प्रतिबंधों के

कारण यह सम्भव नहीं है। मूल्यों में जमीन आसमान का अन्तर बना हुआ है। जो गेहूँ पंजाब में 56 रुपया प्रति क्विंटल बिकता है वह महाराष्ट्र में 150 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है और मद्रास में 160 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है। यही हाल चने का है। पंजाब में चना 54-55 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है लेकिन बंगाल में 145 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है। मध्य प्रदेश में चना 50 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है लेकिन केरल में 150 रु० और मद्रास में भी 150 रु० प्रति क्विंटल बिक रहा है। जब दामों में इतना बड़ा अन्तर होता है तब अनाज के चोरी-छिपे लाने ले जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कभी रात में उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीमा पर या पंजाब दिल्ली की सीमा पर खड़े हो जाएं तो हमें चोरी छिपे अनाज लाने ले जाने के दृश्य दिखाई देंगे इस तरह से कर्मचारियों में भ्रष्टाचार करने का जोष जागता है और हम उन्हें परिस्थितियाँ देते हैं, मौका देते हैं कि एक ट्रक पर 250 रु० लेकर ट्रक को जाने दें। 5 सेर ले जाने वाले को पकड़ लेते हैं। लेकिन ट्रक के ट्रक निकल जाते हैं क्योंकि चैक पोस्ट पर लगे सिपाही और कर्मचारी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं और क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाकर हम इस गंगा को हर एक प्रदेश के किनारे पर बहाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह बात भी साफ है कि क्षेत्रीय प्रतिबंध से पहले अनाज के भाव कम थे और क्षेत्रीय प्रतिबंध के बाद भाव बढ़ गये। सूखे के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसका विचार हम भी न करें, तो भी प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप भावों में वृद्धि हुई है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि इस संकट-काल में व्यापारी तो मुनाफा कमाई की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारें, विशेषकर राज्य सरकारें भी मुनाफा कमाने पर लगी हुई हैं। माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये आंकड़े आये होंगे कि बचत वाले क्षेत्र अपना

अनाज बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं और अगर अनाज बाहर जाने की छूट देते हैं तो उस पर अनुचित मुनाफाखोरी करते हैं। वह अपना खर्चा निकालें, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकारी स्तर पर अनाज जाए, मैं इसका भी विरोधी नहीं हूँ यदि व्यावहारिक दृष्टि से उसे सफल किया जा सके। लेकिन सरकार को कोई दाम की नीति तय करनी होगी। हम आज की स्थिति में अनाज के मामले में सरकार को अनापणनाप मुनाफा कमाने की छूट नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें किसी के अंकुश में नहीं हैं और निरंकुश हो गई हैं। मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूँ चने का। पंजाब 58 रु० क्विंटल चना महाराष्ट्र को देता है और वहाँ पर वह चना 100 रु० प्रति क्विंटल बेचा जाता है। पंजाब से चना गुजरात को 54 रु० प्रति क्विंटल गया और उसको वहाँ पर 80 रु० क्विंटल बेचा गया। इसी तरह पंजाब से चना मद्रास को 65 रु० क्विंटल गया और वहाँ पर 128 रु० क्विंटल बिका। गुलाबी चना मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को 90 रु० क्विंटल गया और वहाँ पर 170 रु० क्विंटल बिका। इसी तरह से राजस्थान अपने क्षेत्र में मुनाफा कमा रहा है। राजस्थान सरकार ने मक्का 40 रु० क्विंटल के भाव से खरीदी और बिहार को 71 रु० क्विंटल के हिसाब से बेची। महाराष्ट्र की सरकार ने चावल 100 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जबकि चावल का थोक भाव 75 रु० से लेकर 90 रु० प्रति क्विंटल तक था। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के नाम पर मुनाफे की अनुचित छूट दी जा रही है। राजस्थान सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटियों को चना बेचती है, लेकिन प्रति क्विंटल 9 रु० मुनाफा कमाती है। मध्य प्रदेश सरकार तो सबसे बाजी ले गई। उसने अपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी को अपने राज्य का गुलाबी चना खरीदने और बेचने का एकाधिकार दे दिया है। अपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी के अलावा मध्य प्रदेश में कोई चना न खरीद सकता है और न

बाहर भेज सकता है। एक मंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश की विधान सभा में बताया है कि अपेक्षा मार्केटिंग सोसाइटी 95 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से गुलाबी चना खरीदती है और बम्बई के किसी आल इंडिया फेडरेशन को 130 रु० से लेकर 150 रु० प्रति क्विंटल की दर से बेचती है। 95 रु० की खरीद, 150 रु० की बिक्री, एक क्विंटल के ऊपर 60 रु० से ज्यादा मुनाफा, वह भी अनाज में और आज की संकट पूर्ण स्थिति में। क्या राज्य सरकारों को सीधी राह पर नहीं लाया जा सकता? मध्य प्रदेश में चना बाहर भेजने की इजाजत केवल कोआपरेटिव सोसाइटियों को है, मगर हर जिले में कोआपरेटिव सोसाइटियाँ नहीं हैं। जो सोसाइटियाँ हैं वे मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हैं। वे किस तरह से चलती हैं इसका उदाहरण हम दिल्ली में देख चुके हैं। राजस्थान में सरकार ने लोगों से वादा किया था कि अगर 40 रु० 50 प० क्विंटल के हिसाब से चना सरकार को बेचा जाय, तो जितना चना सरकार को बेचा जायेगा, उतने चने की मात्रा राज्य से बाहर भेजने की छूट दी जायेगी। लेकिन वाद में यह छूट वापस ले ली गई और राज्य सरकार अपने वादे से मुकर गई।

3 P.M.

खाद्यान्न की दृष्टि से अलग-अलग प्रांतों की दीवारें ही नहीं खड़ी हैं। एक-एक प्रांत में भी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं जिसका परिणाम यह है कि कमी वाले क्षेत्र अलग पड़ गये हैं, बचत वाले क्षेत्र अलग पड़ गये हैं। राजस्थान में मक्का कहीं 40 रु० प्रति क्विंटल बिक रही है, कहीं 65 रु० प्रति क्विंटल बिक रही है। ज्वार का भाव कहीं 42 रु० प्रति क्विंटल है, दूसरी ओर 62 रु० प्रति क्विंटल। मेरा निवेदन है कि नई फसल को देखते हुये इस बात की आवश्यकता है कि क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के सम्बन्ध में निर्णय किया जाय। विशेषज्ञों के भारोमे मंत्री महोदय न बैठें। "कामन सेंस" से काम लें। कुछ खतरा जरूर है लेकिन खतरा

मोल लेने का साहस दिखाना होगा। समस्या केवल अन्न के अभाव की नहीं है। समस्या मनोवैज्ञानिक भी है जिसको हल करने के लिये क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाना बहुत कुछ कारगर साबित होगा।

महोदया, मेरा निवेदन है कि संविधान में संशोधन किया जाय जिसके द्वारा राज्यों के जिम्मे अनाज का उत्पादन बढ़ाने का काम सौंपा जाय। अनाज की बमूली और अनाज का वितरण केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसके लिये संविधान में संशोधन जरूरी होगा। मंत्री महोदय यह आशंका प्रकट कर सकते हैं कि राज्य सरकारें ऐसा संशोधन करने की स्वीकृति नहीं दे सकतीं, लेकिन देश के व्यापक हितों में और दूरदर्शिता के आधार पर आज इस तरह का निर्णय लिया जाना जरूरी है। निर्वट भविष्य में अनाज की समस्या हल होने के आसार नहीं हैं। लेकिन अलग-अलग राज्य सरकारें अलग-अलग नीतियाँ अपना कर इस प्रश्न पर देश की शांति और व्यवस्था को संकट में न डालें, इसके लिये केन्द्र के हाथ में अंतिम अधिकार होना चाहिये। मैं कह चुका हूँ कि आज जब एक ही दल की सब जगह सरकार है तब यह स्थिति है। भविष्य में यह स्थिति बदल सकती है। उसका निराकरण करने के लिए भी संविधान में संशोधन करके उत्पादन का भार राज्यों पर डाल देना चाहिये और प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रिब्यूशन का भार केन्द्र को ले लेना चाहिए।

खाद्यान्न क्षेत्र समाप्त कर दिये जायें और अनाज लाने ले जाने पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा लिये जायें। फूड कारपोरेशन की शाखाएँ सभी राज्यों में कायम की जायें। उसको रुपये की जरूरत है। कल मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा कि आन्ध्र में लोग चावल बेचने के लिये तैयार हैं, लेकिन फूड कारपोरेशन के पास रुपया नहीं है। 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार को फूड कारपोरेशन की रुपये की आवश्यकता पूरी

करनी चाहिये जिससे बचत वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अनाज खरीद सकें और अनाज के उचित वितरण की व्यवस्था कर सकें।

बड़े शहरों में दृढ़तापूर्वक राशन लागू किया जाय। जो राज्य सरकारें इसके लिये तैयार नहीं हैं उन्हें विवश किया जाय। छोटे किसानों के लिये, खेतिहर मजदूरों के लिये बाहर से जो गेहूँ आता है उसके उचित मात्रा में बाँटने की व्यवस्था की जाय।

दूरगामी दृष्टि से पांच वर्ष के भीतर अन्न के सवाल पर देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया जाय और उसके लिये ठोस तथा प्रभावी उपाय अपनाये जायें। खेती के योग्य समस्त पड़ती भूमि को, चाहे वह सरकार के कब्जे में हो अथवा स्थानीय निकायों के, जोता जाय। वनों की खेती योग्य भूमि हल के नीचे लाई जाय। अभी कुल 49.23 मिलियन एकड़ भूमि ऐसी है जो खेती योग्य है, लेकिन उस पर खेती नहीं होती। बड़े पैमाने पर वहाँ खेती का प्रबन्ध किया जाय।

भूमि सुधार तथा अधिकतम जोत के कानून दृढ़ता के साथ लागू किये जायें। किसानों पर नये टैक्स न लगाये जायें। बड़े हुये अभिसार वापस ले लिये जायें। सिंचाई की दरें ऐसी हों जिससे किसान सिंचाई की सुविधा का उपयोग कर सकें। अनाधिक जोतें कर मुक्त करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाय।

अन्न संकट गंभीर है। हम चाहते हैं कि यह समस्या सबके सहयोग से सुलझा जाय। शासन सबका सहयोग प्राप्त करने की बात तो करता है किन्तु इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता। यदि केन्द्र से लेकर जिला स्तर तक सर्वदलीय समितियाँ बनें, लोगों के रोष को, क्रोध को ठीक तरह से शांत करने के उपाय ढूँढ़े जायें तो परिस्थिति गंभीर होते हुये भी उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन शायद वर्तमान शासन से इतनी दूरदक्षिता, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता की आशा करना दुराशा माना है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूँ।

*The question was proposed.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: **There** are 15 amendments. Twelve amendments are in the name of Mr. V. M. Chordia, and three amendments in the name of Mr. Abdul Ghani. Bui Mr. Abdul Ghani is not here. Mr. Chordia may move his amendments now.

SHRI V. M. CHORDIA (Madhya Pradesh) : Madam, I beg to move:

1. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

"and having considered the same, this House is of opinion that the whole of India should be treated as a single unit for food distribution and supply and all the food zones should be abolished".

2. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that arrangements should be made to make foodgrains available at reasonable prices in those areas where State Governments have arbitrarily procured foodgrains from the farmers in the name of levy and monopoly purchase'."

3. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the importance of irrigation schemes should be realised and top priority should be given to them in order to make India self-sufficient in the matter of foodgrains'."

4. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that Government should give up the policy of making huge profits on fertilizers and that, instead, make available to the farmers fertilizers at subsidised low prices'."



[Shri V. M. Chordia]

5. "That at the end of the motion the following be added, namely:—

'and having considered the same, this House is of opinion that corruption and favouritism and, in particular, the lassitude prevailing in the agricultural research institutes should be removed and they should be made more efficient and useful.'

6. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the support price proposed by Government should be determined after taking into consideration the income and expenditure relating to the production from marginal land, and the prices should be so fixed as not to attract the farmers to produce other commercial crops.'

7. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that steps should be taken for devising and manufacturing machinery necessary for agricultural purposes in small fields.'

8. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the recovery from the farmers of minimum monthly charges for electricity used for pumping sets should be stopped, and arrangements should be made for the recovery of only the actual expenses.'

9. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the manufacture of pumping sets required for irrigation purposes should be encouraged.'

10. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that arrange-

ments should be made to provide to farmers power connections for running electric pumping sets'."

11. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the Same, this House is of opinion that concrete steps should be taken to relieving the farmer from mental worries and indebtedness'."

12. "That at the end of the motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House is of opinion that the Ministries of Agriculture in the States should be under the direct charge of Chief Ministers or Senior Ministers'."

*The questions were proposed.*

SHRI ANAND CHAND (Bihar) : Madam Deputy Chairman, the Motion was one for consideration of the food "situation in the country, but my hon. friend has taken most of the time in emphasising the difficulties or the shortfalls which in his opinion, the country and the cultivators are facing because of the promulgation of Single State Food Zones. I should have thought that in a discussion of this kind he would have brought the whole policy of food production, distribution and imports into the orbit of this discussion so that the House would have had the chance to debate the problem as a whole. Anyway, since he has chosen only to point out certain defects which, according to him, are standing in the way of distribution, I would try, within the limited time at my disposal, to put before the House the other side of the picture.

Shri Vajpayee has been at pains to explain that, in his view, there is no paucity of foodgrains as such in the country, but there is maldistribution.

SHRI TAL BIHARI VAJPAYEE : I quoted the Prime Minister. I did not say anything like that.

SHRI ANAND CHAND : That was the impression that I at least got.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : A wrong impression.

Stall ANAND CHAND: In my opinion it is not so. We are facing a serious shortage of food in this country. The question is not one of only distribution. The question is also one of increased production. The 'figures that have been given in 'the Review of the Food Situation' from which he quoted, make it absolutely clear that the food deficit last year was to the extent of about 7 million tonnes. And this year it is going to rise to the tune of 12 to 14 million tonnes. Now, Madam Deputy Chairman, although from the chart of distribution one can say that the average per capita availability of food might be about 13 ounces, which is supposed to be the basic minimum under these circumstances, we must not forget but we must always bear in mind this factor, that in India unlike in other countries, we have not got supplementary foods like eggs and milk, to supplement these cereals. Therefore, the intake of 13 ounces which at the present moment is the food supplied to us, is not enough in this country without the subsidiary foods being available at cheap and economic rates, to keep the body moving or to produce the calories that go into working the human body for >4 hours.

Shri Vajpayee has been at pains to explain, and I myself had some doubts which I expressed the other day when speaking on the motion of Thanks to the President's Address, that with the food zones as they are now, where practically every State is cordoned off into one food zone, there is restriction on the movement of foodgrains from one State to another and that we are not, in my opinion, adopting a national policy so far as food is concerned. That was my view, and that remains so, to a certain extent. But when we look at it in the present context of things we must not forget, what would be the result if the food zones were abolished altogether and immediately. One effect, to my mind, would be increase of prices all round. Shri Vajpayee was at pains to explain that prices would fall or tend to fall, because in certain areas at the present moment food is available, foodgrains are available. He said gram grain was available in Punjab, that it was surplus, but they were not selling it because they want higher rates. On the other hand he says if the movement of

foodgrains is made free in the country and if it is in the hands of the private trade then the prices of foodgrains would fall. These two things are not complementary to each other. If today there is hoarding because they want higher prices than if the food zones were removed tomorrow, then there will be profiteering on a large scale. The prices will not go down. My hon. friend also made the point that so far as some particular areas are concerned, the availability of foodgrains is there, but the purchase machinery is not there. I may respectfully point out that there is this purchase machinery in the States. There is also this Corporation which has been established by the Centre. But at the present moment paucity of foodgrains is there. In the end he very rightly pointed out that he wanted distribution plus the purchase of foodgrains in this country and that the matter should be taken over by the Union Government. So far so good. But this poses two very important problems. One is the problem of finance and the other is the administrative problem. Wherefrom is the centre to produce the tremendous finance that would be required if you want the foodgrains in each of the surplus States and in each surplus area, to be procured and sold by the Union Government? Secondly, is there going to be a duplicate machinery of administration so that this procurement may be effected in each State? Agriculture is—and rightly so—today a State subject. In this direction the Centre or the Union Government has to work with the utmost cooperation of the States and this can only be done if there is harmony and not disharmony between the Food and Agriculture Ministry at the Centre and the Ministries in the States. Therefore, to a very large extent, we have to depend upon the administrative machinery which is at present functioning in the States so far as procurement and distribution of foodgrains are concerned. Of course, the movement of foodgrains from one area to another is there. Those areas which are happily today surplus in foodgrains are sending their foodgrains to the deficit areas. When there was scarcity of rice in Kerala, the adjacent States in the Southern zone came to its aid and rice was moved. There is no question of this not being done. The position is this. If these food zones are abolished all at once, then it will be just loosening the flood-

[Shri Anand Chand] gates and the prices will go up all round and there will be no stopping them.

Madam Deputy Chairman, with your permission I will mention certain points which my hon. friend did not mention but which I think are pertinent to the debate which is now going on in this House. It is true that food production in this country has not been up to what it was anticipated. The First Plan had a certain target, the Second Plan had its certain target and the Third Plan, of course, has a target which is higher than that of the Second Plan. We must remember that when we mention these targets that are there in our Plans, the targets that are mentioned are the potential targets. In other words, when we state that by the end of the Second Five-Year Plan, the potential target would be something like 92 or 95 million tonnes, it did not mean that 95 million tonnes would be produced in the country. The potential target meant that given all the facilities in this matter of manures, in the matter of seeds and in the matter of human effort, it would be possible to produce 95 million tonnes at the end of the Third Five Year Plan. And along with those important incumbents that I have mentioned there is one more very necessary incumbent, namely timely rains in the country. The monsoon in India has always been erratic. Last year, of course, it had been more erratic than in any year perhaps in living memory. It has always been erratic and it is to supplement that deficiency that the Union Government and the State Governments under these Five Year Plans have launched upon large-scale, major, medium and minor irrigations. In certain fields, of course, we have met with success. Take for instance minor irrigation. In the First Five Year Plan the target was 11.2 million acres, and the actual achievement was somewhere to the tune of 9 million acres. In the Second Plan the target was 9 million acres and it was achieved fully. In the Third Five Year Plan the target for minor irrigation is 12.8 million acres and the achievements are expected to come to round about 13.1 million acres. So, we cannot just say offhand that nothing has been done so far as this particular problem is concerned. Let us see where these shortfalls lie, why we have not been able to achieve the

approximate potential which we aimed at. If we go into this question a little more deeply, we will find that it has really been the fertilisers, which have brought us down, which have brought down the production of food in this country. Madam, regarding fertilisers the question can be asked, when it was estimated that the planned capacity would be something like six lakh tonnes, why has production been only to the extent of four lakh tonnes? There again, it is a question of continuing the process. I think we forget that in this or any planning, when we put in a certain date, when we put in certain finances, there are certain other aspects also to be considered. Take, for example, electricity. When we say that a particular project is going to yield two million Kw. of electricity, it does not follow that it is produced in that particular year. Sometimes it is achieved in another year following or in the following years, or the following couple of years but the yield is achieved really and certainly. In the same way, in respect of fertilisers, when the capacity was aimed at six lakh tonnes the idea was that it would be produced purely by State enterprise. It could not be done and the private sector also did not take this up because the profit was not much. That is the reason why now the private sector has been introduced into the question of production of fertilisers. I know there has been a lot of criticism about it. The Prime Minister today answers it and she said that to a certain extent it might be cheaper for people from outside coming and putting up this thing. It is a healthy thing also because if Government by itself is not able to produce then at least if a factory situated here produces fertilisers in this country, we will not have to drain away our meagre foreign exchange resources to import these fertilisers from outside, an import which is a big drain on our economy. So, I hope that in the days that lie ahead, in the years that lie ahead this lag will be made up and with increased fertiliser production, the production of food per acre will rise. This is the only way in which we can meet the present food crisis in the country.

One word more before I resume my seat. There is a programme for the installation of wells, I believe something like a hundred thousand wells electrically operated

are going to be put up, which would irrigate another three million acres. There is a problem before the Government for the revival of the Krishak Samaj, the Cultivator's Forum that were in existence. I know that they have been dormant in certain areas. It was a good idea but it was allowed to remain dormant. I hope the Food Minister will take more interest in it now that he is closely associated with it to revive it. There is the problem of the Young Farmer's Association which, I believe will be able to help and then there is the idea of the Tonnage Clubs where every farmer who is able to produce a certain amount of foodgrains per acre which exceeds a certain tonnage can become a member thereby developing discourse and intercourse between each other pool the knowledge in this particular respect. This would help production to a large extent. All these things will, of course, take time. The basic question is: time being short what has to be done to meet the deficit which we are facing? I think the Government could not have done otherwise than what it has done, one, it has to emphasise greater production per acre and two, take in imports from wherever they are available. It is not a question of begging, as the Prime Minister said. This is a question of bare necessity, this is a question of interdependence. Therefore, I hope that in the times to come we will solve the problem to the satisfaction of the people of India.

Thank you.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : Madam, I think the House will be grateful to our friend, Shri Vajpayee, for focussing the attention of the House and of this country on this problem. In fact, this is a problem which has been with us since independence. One wonders why this country which, before partition, in the British Empire used to feed the Empire, was the granary of the Empire, has become a country that should beg for food every time. This is the achievement after eighteen years. Even the late Prime Minister, Pandit Nehru, warned the country more than once and his planners that if we failed on the food front, our Plans would be nowhere. It seems his warnings were not heeded to Or sufficient attention was not

paid to the warnings. And, why? There is a section of opinion, more than, a section a class, which has developed an interest in controls. They want controls over everything. Even though this policy of controls has been tried and has been given up because of its failure, whenever there is a shortage, failure of rains, they want controls imposed again. A vested interest has developed for this type of controls, whether it is a control on sale or zonal restriction or anything. My hon. friend, Mr. Vajpayee, rightly pointed out the greed of the State Governments to make money from another State Government, the greed of a State which takes advantage of the circumstances of a deficit State and charges more. This can only happen when we have these restrictions, zonal restrictions as well as restrictions on sale and purchase. The Government machinery is always slow and faulty. We were hoping that the Food Minister, after he took charge, after he had talked with the Party Leaders. I think it was in July or so last year, would bring in a new outlook and would tackle the problem with a little more imagination and in a new way. Unfortunately, his task has been made more difficult because of the drought that we are suffering from but is it only drought? Is the Food Minister not a prisoner of his ideas, of a machinery, of a doctrine and of people who want to follow such doctrines, because of which he is not able to change the situation? Looking at the papers, Madam, one feels very sorry. The other day I was looking at a paper while I was going to Madras in the plane I was given "The Free Press Journal" and there is a small news item there. One should be grateful to the countries that have come forward to help us but what about us, what are we doing when we have come to this stage, when we are begging in this condition before the whole world? Italy's National Television and individual newspapers have collected about 6,000 lire, that is Rs. 4.7 crores of rupees, to help India solve her food problem. The independent news paper "La Stampa" said that it had sent three plane loads of food to India and twelve more would follow. From the Vatican City, His Holiness the Pope will on Sunday send twenty-two lorries destined for India with food supplies. We are grateful to His Holiness in that he has come forward in the time of our need to

help us but where does it put our country ? From Oslo, Norway, to-day the news item says that Oslo has decided to grant 2.5 million kroner, that is about Rs. 1,700,000 worth immediately of famine relief to India. This is a Government announcement.

Where are we ? We are like beggars standing before the whole world.

SHR! P. K. KUMARAN (Andhra Pradesh) : Shame.

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore): Not at all.

SHRI P. K. KUMARAN : Very good; you go in for it.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : This is the beginning. The whole world is doing it. It makes us feel ashamed that we are unable to manage our affairs properly and why ? Have not other countries managed their affairs properly ? Have not other countries improved their agriculture ? Have not countries which had a backward agriculture become the most productive and have they not started earning foreign exchange out of their export of rice, out of their export of food ? Why don't we learn from them Madam ? It is this obstinacy that is coming in the way and I was hoping that the new Food Minister would be able to give a new look to this situation and change. We may perhaps have a little more patience and sympathy with him to help him to tide over the difficulty but the patience of the people cannot be tried indefinitely. The Food Minister and the Congress Government had better remember that the French Revolution came out of a situation of starvation of the poor people. There was wine flowing, there was food flowing, there were dances, there were poets and writers, in Paris. Paris was very affluent but when the people did not have food, came the French Revolution. So this Government had better take a lesson. This morning we had the Prime Minister's speech and all that we got was this:

हाँ जी, हम यह जानते हैं, हमें पहले भी कहा गया है। अगर जानते हैं और पहले भी कहा गया तो आप बात सुनेंगे नहीं तो लोग अपना इलाज कर लेंगे। Ma

Madam, this country has been bled white in taxation for building river valley projects. How many of them are producing what they were supposed to ? Are they

giving us enough water and irrigation ? And it is the greed of the State Ministers to collect heavy water charges that comes in the way of agriculturists. All this should be scrapped. The agriculturists, the small agriculturists should be given encouragement. He should be given advice because the bulk of our agriculturists is not sufficiently literate. I hear sometimes in the evening the radio giving hints as to what to do. I do not know how many of the poor agriculturists ever listen, whether they have the radio and whether they have the time to listen. I know the Congress election machinery is being spread all over to the villages and at the time when the agriculturists are at home their propaganda is spread through the radio and at the time when the poor agriculturists are in the field this sort of hints to the agriculturists are being sent. Who hears it and how does it help the poor agriculturists ? It does not because the basic idea is not to help the agriculturist.

Madam, this morning there was my calling attention notice about the Narmada Valley project, and how the Minister dodged the question. We will be patient with the new Minister; perhaps he has not found his feet. But why was Dr. K. L. Rao hiding behind when he has been in the know of things ? Two years ago he came to Gujarat to meet the Chief Minister. At that time Dr. Ivaraj Mehta was in charge. He met the members of the legislature and he assured us that the Narmada scheme will be taken in hand early. It was at that time that I pointed out to him that just before the first elections the Government of India promised Gujarat the Tapti scheme and before the second election the Mahi project. And both of them are still hanging fire, undone and incomplete. Now that the next election is ahead they have come up with this Narmada scheme. Madam, the Narmada scheme has a history behind it and few Members would know it. A retired engineer of the Central Provinces Government under the British regime—Mr. Wadia. I think was his name—had prepared a scheme. He went round from door to door to everyone of the new Congress Ministers after the new Congress Government was formed and explained to them that this was the one scheme that could give an immediate return and the largest benefits to this country not only for agriculture but

also for development. The Narmada river would become navigable right up to Jubhulpore. You will get a quantity of electric power that you will not be able to use for years; you will get enough power to develop the aluminium resources in the valley and what not. But the Congress Ministers would not look at it. The matter was bungled and the scheme was put into the cold storage because each one of the Provincial Governments wanted their own pet schemes and no one benefiting everybody. Here Dr. K. L. Rao is faced with the same problem. Every State wants to put a spoke in the wheel and some of them—I am sorry to say—like the dog in the manger. The Maharashtra Government has the least land to lose in this Narmada scheme; yet they must also put a spoke in the wheel apart from Madhya Pradesh which loses a large amount of agricultural land. This is a matter that can be settled with Gujarat. If one State loses a couple of acres of good agricultural land, the river valley project gives you lakhs and lakhs of additional acres for cultivation. What is the Central Government doing? Will they just go on sitting idly and watching the situation? At this rate they will never be able to solve the food problem. It is necessary that the matter should be pursued with a new spirit and schemes of this type which will give us more food quickly should be taken in hand and implemented fast. The many schemes that have been hanging half done should be completed. Instead of planning more and trying to put in more money in new schemes, if the schemes that are already in hand are completed, Madam, there will be great relief in the matter of food production.

It is quite true, Madam, that encroachment has been made on the land available for food production by cash crops but there is plenty of land in this country yet, even with all this development. In Bihar, there is plenty of land. On some of the rivers I know of enterprising farmers who have gone and settled on land because there the rule is, a man who is able to show that he has been cultivating the land for two years and paying revenue becomes the owner. After the abolition of the zamindari this rule has been put in; only the people do not know it sufficiently. If a thing like this was known to the people, if the refugees or people who are displaced

from elsewhere were told of this, I am sure Unit lots of people would go and settle down there because a large portion of the land there is on the rivers where water comes from the Himalayas and water is available all the time. Does our Government try to do anything about it? Has the Government tried to attract people, agriculturists, to go and settle down there and grow food? At one time there was a talk that the food portfolio of the States should be held by the Chief Ministers. But the Chief Ministers are interested in much more power, in much more manoeuvring and having a say in all matters and telling Members of Parliament of their States where they should vote and where they should not, whether they would be given tickets next time or not, and how they should behave instead of concentrating their attention on the production of good. That is the reason why we are going down every day. Madam, it is a sad story that so many years after freedom the State Governments have to resort to firing on people who are asking for food, that a little boy should lose his life because he was in a crowd that was asking for food. That shows the extent to which the callousness of this Government goes. There can be no ice for this callousness. It is utter incompetence, utter neglect and indifference to the needs of the people. As long as they get the vote every five years, they do not care.

That is the attitude of the Government and that is what needs to be changed. While I personally would like free enterprise to flourish, a free peasant to flourish, I would not be opposed to the Government directing a peasant, telling him what to do, if he is told efficiently, if he is told what to do in time. That would help us to solve our food problem. But we have not got an efficient machinery to educate the farmer. We blindly copied an idea of giving land to the tiller. After having given him land, the poor peasant does not know what to do. So, he produces what he can, even though he could produce much more from the same piece of land if he was told how to do it, if he was told what to do and when, if better seed was available and if fertilisers were available. This is what the Government should do. It is doing very badly in all these respects and that is why we have this situation when, after so many

[Shri Dahyabhai V. Patel]

years of freedom, we have to use bullets on our people who ask for food, when we have, to go with a begging bowl all over the world. India is the biggest beggar in the world. Everything you want. So far it was only money. From this year it is begging for food. What a shame to the country ?

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Madam Deputy Chairman, I heard with great earnestness the two great speeches made from that side of the House on the food problem of the country. They also admit that this is a very grave crisis so far as the food problem in this country is concerned. We are facing a mighty crisis and how to get over the crisis ought to have been the approach of our two friends, instead of capitalising on the situation for political purposes.

Now, my good friend, Mr. Dahyabhai Patel, for whose birth and blood I have got great respect but not for any of his politics, has been proclaiming from this House that India has been reduced to a state of beggary so far as food is concerned. India, he says, is the biggest beggar for food. And he was also pointing out the various countries which have made their contribution by giving relief to the famine-stricken people of India. He was also acknowledging with thanks and with gratitude the various forms of help that was sent to us, but at the same time he was accusing that India has become a beggar today. How can he reconcile these two stands of his ? I would like to know it. Was he telling it . . .

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): It is difficulty in understanding.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Except that it was for political purposes, these two stands of his cannot be reconciled. He was grateful for the help rendered by those people and at the same time he was condemning the Government of India. . . .

SHRI LOKANATH MISRA: The point is. the only difference is some difficulty in the understanding of the hon. Member.

THE DEPUTY CHAIRMAN : What do you want?

SHRI LOKANATH MISRA: I would explain it to him. I am only acknowledging it-  
(Interruptions)

SHRI N. SRI RAMA REDDY: This stand is no good. Capitalising on a grave crisis for political purposes is absolutely no good. Does he or does he not know that there has been a devastating failure of rains this year causing the greatest havoc on food production . . .

SHRI LOKANATH MISRA : And who is responsible for it ?

SHRI N. SRI RAMA REDDY ... in a century. For rain, not you and not I, it is all a mystery of the sky.

SHRI LOKANATH MISRA: Irrespective of your Five Year Plans in the past eighteen years ?

SHRI N. SRI RAMA REDDY: In a century such a great failure has not occurred. Does not my friend realise that in a century, for the first time, such a great havoc, natural calamity, has occurred in this country on account of the failure of rains? This is recognised by all, not only in this country. I would like to know whether our hon. Member. Mr. Dahyabhai Patel, does not have the patience to be here. I would like to quote from the authority of the Food and Agricultural Organisation about what the situation is. It is not only in India. There has been a great failure in Australia. There has been a great failure in New Zealand, in Africa, in Europe and everywhere else. The whole earth probably has moved on to a situation or belt where rainlessness prevails this year. I do not know and I cannot explain it. The situation is that everywhere there has been failure of rains. (Interruption). Please do not disturb me. I will quote from here and let my friend opposite note it. From 1934 to 1938 Latin America had a surplus of nine million tonnes every year. During 1960 all the surplus was wiped out and today they are in a great deficit. I am quoting from the FAO and it is not mine. Similarly, during 1934-38, East Europe, including the USSR, had a surplus of five million tonnes. During 1960 the USSR and other East European countries are deficit to the extent of 14 million tonnes of food. Will you say the same thing to those countries ? Do you think that only on account of the Governments of those countries such a situation has arisen ?

SHRI LOKANATH MISRA: That is not capitalising ?

SHRI N. SRI RAMA REDDY : During 1934-38 in Ash there was a surplus of two million tonnes. In 1960 the deficit in Asia was 16 million tonnes and in 1966 the deficit is 30 million tonnes. Similarly, the situation in Africa is not any better. Therefore, it is an extraordinary calamity that we have been called upon to face and my hon. friends on the Opposition Benches should, give their co-operation to solve this grave problem.

My good friends, Mr. Vajpayee and Mr. Patel, have been saying that there had been shooting when the people had been asking for food, that this Government had been answering them with lathis and bullets. Far from the truth. Of course, I very much regret that a boy of ten years died on account of firing. Do you mean to say that if the intention of the Government was to answer hunger-marchers with bullets, a boy of ten would have been aimed at to be killed?

SHRI LOKANATH MISRA: They want to reduce the population.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Certainly this is belied. Probably it is for other reasons. I do not know. I am not well posted. Probably Mr. Subramanian! will be able to speak well on the matter, but my very common sense tells me that a boy of ten years could not have been the target of attack by the Government in respect of hunger-marchers. The people would have been dealt with in a much better way, if only it was not for reasons other than answering hunger-marchers with bullets and lathis. Please, for heavens' sake do not make such ungenerous remarks. Please co-operate and let us see how many countries face this situation. More than half of India is facing this situation and has been affected by drought. The result is that production has fallen down tremendously. Mr. Vajpayee was talking to us, but let us estimate what the shortfall in food production is. What is the food budget? He himself did not say it. I would like to tell him that last year we produced 88.5 million tonnes of food. On top of it we imported 7 million tonnes of food-grains. All this was consumed by the people. Last year nearly 96 million tonnes of food was consumed. This year we have hardly produced 76 million tonnes, according to the estimates. That means 20 million

tonnes is the shortfall this year, on account of the drought conditions prevailing in the country, not only in this country but also in other countries.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Even the Minister does not claim a shortfall of 20 million tonnes.

SHRI P. K. KUMARAN: Even the Minister does not say so.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: It is all based on facts and figures. Anybody can justify these facts and figures. These are not myths that I am quoting. Of course, I am very glad that attempts are being made to cope with the situation arising out of the shortfall of 20 million tonnes of food. The other countries have been good enough to share with us our great short-fall this year, and probably 10 million to 12 million tonnes of foodgrains he is going to import. For another 10 million tonnes he has got programmes. I do not know if my good friends have seen this book. He has programmes for producing high-yielding varieties of foodgrains. This book has been placed with us. Lands to the extent of 4.5 million acres are proposed to be brought under various hybrid varieties of crops like Taichung Native 1, Tainan 3, hybrid maize, hybrid jowar, hybrid bajra, etc. All these are high-yielding varieties. I am absolutely certain that a great innovation has been brought into agriculture. The capacity of these hybrid varieties is enormously great. They give three or four times more yield per acre. I am sure that with the introduction of these varieties we will be able to step up our production. Another probably 10 million tonnes of foodgrains are going to be produced by this scheme. This is a new technology that has come into our country. It is spreading like wild fire. Every farmer is taking to it. In place of only 5 or 6 quintals of bajra or 3 or 4 quintals of maize yields today, it will yield up to 40 quintals. Such programmes are being taken in hand. After all in a country where there are 65 million farmers, you cannot educate them overnight. You cannot revolutionise them overnight. You cannot do that. Probably you will only create trouble by that. But it is a question of taking to new ways of technology, and it takes time. But I am very happy that in spite of the fact that there have been trouble creators in our country mainly for



[SHRI N. SRI RAMA REDDY] the sake of politics and not at all in the service of agriculture, in spite of that, I am absolutely certain that people are going to take to this new method, and we are going to solve this problem. I am saying this because of my own personal experience. I have taken to the production of hybrid maize and it has come up exceedingly well. Today I have received a letter saying that the District Collector came and saw my farm along with nearly two hundred people and they felt so happy to see an enormously good crop within only 30 or 40 days. The innovation itself is a recent one. Five years before this was not known. It is now spreading I am sure it is going to save us. This is a challenge. Really the crisis is a challenge and we are going to face it. We are going to see an enormously good crop within successful. This is a challenge opportunity to educate the people, to make people take to new methods of agriculture and see that the country is self-sufficient. We should; not be getting defeatist, we must not develop cold feet we must be courageous. I am sure if only my friends give up these politics and concentrate on food instead of simply criticising, night and day, things will be all right. What an ungenerous statement has been made by my friend. Mr. Vajpayee, when he said that the Food Minister in order to make his own opinion prevail appoints experts of his own class or his own relatives, and that he makes them say what he has in his mind.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I did not say anything like that. What I said was that if the experts do belong to the Ministry of Food and Agriculture, they are likely to be influenced by the view of the Minister. I did not say that he has appointed his relatives. The hon. Member did not understand me.

SHRI N. SRI RAMA REDDY : Anyway at least I am very happy for the correction.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He should correct himself. He did not follow my speech.

SHRI N. SRI RAMA REDDY : I have taken, the English translation here. I am saying this after following the English translation. You may accuse me that I do not know Hindi. Anyway I am happy, ir

is ungenerous to say that. He is as much a patriot as you are. We want solutions to the problems of the country, not political slogans. That is why such ungenerous statements should not be made. We are all after one problem, that is, to make this country self-sufficient in food, and that shall be our aim instead of trying to pick holes and doing every sort of thing. That is not generous.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What a tragedy he is the Secretary of the Congress Parliamentary Party.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: That has not made me any less patriotic than anybody in this country or in this House.

Madam, agriculture is a slow process, everybody knows it. In this country particularly out of 340 million acres of sown area 250 million or 260 million acres entirely depend upon rainfall. If the rainfall fails. Mr. Vajpayee or Mr. Dahyabhai Patel has to complain only against God and not against Mr. Subramanian!. Please pray for better rains and the problem will be solved. Anyway, efforts are being made in other directions also. In spite of that I would like to earnestly appeal to the Food Minister that the Indo-Gangetic plain can feed the entire nation; there is an ocean buried under the soil of the Indo-Gangetic plain. One tubewell could irrigate thousands of acres. Therefore, the solution of the agricultural problem of this country is to go into this question and get the Ganga from under the soil. There is plenty of Ganga water under the soil. Please make an attempt and give 1 lakh of tubewells to U.P., 1 lakh to Bengal, another lakh to Bihar and another lakh to Punjab. In the entire Indo-Gangetic plain there is such a huge quantity of water and I know it. Therefore, if you take out the Padala Ganga, you are sure to solve this problem of agriculture. After ten years there will not be any more problem. We are not going to depend upon the skies any more, because there is plenty of Ganga water under the soil.

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala): He is talking of Padala Ganga. Who will be Bhagirath ?

SHRI N. SRI RAMA REDDY: I suppose I am not raising very many controversies, but all the same I would like to

point out to the hon. (Food Minister that I am not happy with regard to the efforts that are being made for internal procurement, though his efforts for procurement from outside the country has been an enormous success. I would take this opportunity of offering my grateful thanks to all those countries that have responded to our call in this hour of great crisis. Those countries are helping us in a "very big way. I am very grateful for that, but I would like to tell my friend, Mr. Subramanian! that with the efforts that are being made to make an effective internal procurement I am not quite satisfied. The procurement has been very lethargic. It has not been as satisfactory as it ought to have been. Therefore the tempo of internal procurement must be increased. Further there is a snag. As was pointed out—Mr. Vajpayee or Mr. Patel, I do not know which of them raised that topic—the question of more control in the field of agriculture from the Centre is very important. It might be that the Constitution provides that agriculture is a State subject and the Centre cannot do anything. But if there is any shortage indents for greater amount of food are simply thrown at the face of the Food Minister of the Government of India, and they think that is the responsibility of the Centre to supply them enough food. Not enough effort is being made

either for more production or P.M. more procurement. Therefore, I

say that something has got to be done. So I have given notice of a Resolution that there should be an Expert Committee appointed to go into all these problems in an integrated way and see what can be done in the matter.

They were complaining of the zonal restrictions. Without zonal restrictions, what would have been the fate of the country? •Complete anarchy. It is possible now by making each State a zone, to identify the areas of shortfall and the areas of surplus and it is possible to make efforts to procure, to make effective procurements, in surplus areas and distribute in areas where foodgrains are needed. But if the whole country, the entire continent is thrown open as one zone, what is going to be the fate of the country? Even with State trading, even with zonal restrictions, my friend was M21RS/66— 5

complaining of the disparity in prices from Punjab to U.P. from U.P. to Madras and from Madras to West Bengal. All these difficulties, whether they are right or wrong.

PROF. M. B. LALL (Uttar Pradesh) : He was not pointing out the disparity in prices, he was pointing out the profiteering by the State Governments.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Profiteering wherever it is, is bad. It has got to be condemned. I do not know whether the Government resorts to profiteering. It is rather difficult for me to believe that Government, in this hour of great crisis, takes to profiteering. It is enough if it saves 'JS from this situation. It is enough if it gives us some food to eat and saves the country. But if anybody says that the Government takes to profiteering, it is difficult for me to believe it. I do not have any figures. If you have any figures, please talk to the Food Minister. I am not going into details. He is the authority.

(Interruptions)

With regard to rationing, rationing is a must. Unfortunately this country has been called upon to face very many situations. We expected that the Himalayan mountains were going to give protection to this country for all time to come and unfortunately, the Himalayas had to be protected on account of the treacherous act of China. We expected that the farmer in the village was going to produce food and that food we could procure and distribute in the urban and non-agricultural areas and thus save the country. But it is the ryot and the small farmer in the village who are now required to be fed by Shri Subramanian!

THE DEPUTY CHAIRMAN : You have taken 20 minutes.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: This is the situation which we are facing and we shall try to solve it as best as we can.

I would like to caution my friends not to cross the limits of decency in either trying in their attitude to capitalise on politics . . .

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He is talking nonsense.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: . . . for their political . . .

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What is he talking? Who has crossed the limits of decency? Perhaps, he does not know what decency means.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That remark was not called for and proper at this juncture. I do not think that you should reflect in that way. Nobody crossed the limits of decency.

Shri Khandubhai Desai.

SHRI KHANDUBHAI K. DESAI (Gujarat): Madam Deputy Chairman, particularly this year we are face to face with a difficult situation as far as food is concerned. I would not like to go into the detail about the neglect or what has been ignored during the last decade in the matter of food and agriculture. The present Minister may not be wholly responsible for the difficulties which we are passing through. And I am afraid, because of past neglect, the food situation in the context of our agriculture, would have to be faced for nearly a decade more.

At the outset, I would say that now we are passing through one of the worst times as far as the food supply is concerned. Within a short time, Government must make up its mind regarding the food problem, in a long range way. The only year in which, I remember, we were out of difficulty was the year 1955, when the prices were low and we had to give price support. Then we became complacent and concentrated more on sophistication, on large industries, and other things. I do not mean to suggest for a moment that we should not have gone in for industrialisation. But some of us often and on pointed out on the floor of this House to the Planning Commission and the planners that the development of agriculture and food and industry should go *pari passu* so that an imbalance is not created. The present food difficulty is mostly due to this imbalance. And particularly this year we are facing Unfavourable nature. Even if we are not faced with unfavourable nature, still the food difficulty would have been there. We have been importing from year to year more and more food from outside, from two million tonnes per year to nearly 10 to 12 million tonnes this year. Even last year when it was supposed to be a bumper crop and when the nature was so favour-

able, we had to import seven million tonnes. It is not good. Nature, this time, has shaken us from our slumber, I think. Therefore, it is time now, when the Fourth Five Year Plan is still in the making, that more attention is paid to food and agriculture.

The difficulties that the country is facing in regard to food and agriculture in all its aspects also jeopardise the industrial expansion which we have experienced during the last year. Most of the industries, as we know, are based on agriculture. Agriculture and industry go together and any improvement in agriculture will not only give us food but the improved methods and the opening of the mind of the peasantry will also give us better industrial raw materials.

With little hesitation, I might also say that whoever was inspired by or thought of the food zones, has tendered the greatest disservice to the nation. But after this is done, I do not think it is wise for us today to criticise it any further but we should see as to how best we can get out of the difficulty which is more or less man-made. It is very difficult to convince the people of the deficit area that they should get wheat or rice at nearly double the price at which it is available in the surplus area. Let us see how this country in the matter of agriculture and industry is situated. Fortunately, for us every State has got some surplus in one commodity or other. Some States have got surplus corn, some have got surplus cotton, some have got surplus oil-seeds, some have surplus coal, some have surplus jute and so on. Now, Kerala has got surplus export trade. Suppose this particular scheme of considering every surplus State as a sovereign State under the charge of a Chief Minister comes into being, what is going to happen to this country? It is bad. It will set in motion disintegration, to say the least. To say that every State should be self-sufficient in food is to talk of the impossible in away for the time being because land water and rains are not equally distributed. Some land and some climate are entirely suitable for a particular type of crop, which is good for the nation. And, therefore, I will plead with the Government that sooner the zones are abolished the better it is for the country in every way.

Then, Madam, I would like to say that the estimates of deficit in food and surplus

in food in state zones are also not correct. When a psychology of scarcity is created and different zones are created, it is but human for the Chief Ministers and the Agriculture Ministers of those States to exaggerate their deficit. The surplus of the States is shown as less and the deficits are shown as more, and therefore, according to the figures that are made available to us, the deficit in the country as a whole is multiplied which again creates a vicious circle and creates a psychology whereby everybody goes on exaggerating.

Then, Madam, let us understand that our country is a country of small peasants. The Nagpur Resolution on paper has recommended co-operatives.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh) :  
Cooperative farming.

SHRI KHANDUBHAI K. DESAI: I am just coming to it. Now, Co-operative farming is a substitute for large-scale agricultural production, and we want to imitate, if we can, large-scale agriculture by tractors and what not by imitating what is happening in some of the countries of the new world like Brazil, Argentina, Canada, United States, etc. It is nearly ten years since we passed this Resolution, but we have not been able to see it through. The peasant is very much attached to his piece of land, whether it may be 5 acres or 10 acres. That does not mean that I am against co-operative farming. That is probably the best way. But idealism and practice differ. The peasantry would have to be educated. Till then what is to be done? You cannot wait as far as food is concerned. Therefore, some alternative also should be thought of, namely how to make the small peasant and the small farmer utilise the smaller instruments of production instead of abandoning the whole idea of co-operative farming. You have imported so many tractors, big tractors. They are lying idle, as I understand, for want of spare parts, and even, I am given to understand, for want of good know-how and good technicians to work them. Anyway, it is not just crying over spilt milk now when we have found that we have failed in so many aspects during the last ten years. Let us not repeat that mistake again but plan agriculture in a way so as to yield more food.'

Madam, I come from a peasant family. All my relatives are themselves peasants. Two or three of them I know particularly. They are able to produce on their land 2 to 2½ times of what they produced earlier. So it is possible. It can be done. It is good that with the Food Ministry has been merged the Ministry of Community Development. I do not know why it was not thought of earlier. A lot of people, young-men, with some agricultural frame of mind, what are called village workers, had been vegetating all these ten years and wasting their time and money of the country. What the farmers require is rudimentary education, how to produce more. The village workers should not go on sermonizing them. There are progressive farmers who know their job, and once the scheme is placed before them they take to it.

Madam, we have been hearing a great deal about chemical fertilisers. Of course, chemical fertilisers is a must. I have no doubt in my mind about it. But at the same time organic manure in the form of millions of tons of cowdung or animal dung, that is being burnt, could have been saved. That could be done only by education. If green manure could be mixed up with chemical fertiliser according to the best technique it would be better; otherwise it is said that if chemical fertilisers alone are used without the proper admixture of organic manure or green manure, the land is spoiled. I do know-how, but that is what is being said by the agricultural experts. When I again suggest the saving of millions of tonnes of organic manure, I had suggested it on the floor of this House about seven years back. There is no use of again talking theoretically, because 'domestic Kitchens' is a continuous affair, and domestic kitchens are increasing every day owing to the large increasing population. Now they have to be given a substitute 'domestic fuel' and I suggested about five years or seven years back that we have got in this country large deposits of low grade coal. Now at least, it will be a good investment to make, and the investment should be made in turning the low grade coal into domestic fuel, soft coke as it is called, low carbonised coal as it is called, and the result will be that while producing low grade domestic fuel in the mines you will be creating various gases; you will be having a lot of by-products also. All that

[Shri Khandubhai K. Desai] would have been done then. I made an enquiry some time back in the Planning Commission as to what had been done about that proposal. I was informed that there were different opinions that some pilot plant was being thought of at the Central level. Now for food and agriculture I think substitute domestic fuel also must go side by side, and the village people must be educated to use this soft coke for their kitchens. This is also a suggestion which some of us have made repeatedly on the floor of this House. But very little attention has been paid to it. As I said in the initial stage, let us not be complacent and think that there will be good rains next year or the year after and that the food problem will be solved within five years. That way I am not a pessimist, but I must say that the food problem will be with us for nearly a decade because, even if the initial steps are taken immediately as an emergency, it will take quite a long time before the improved method of agriculture the improved utilisation of manure and the improved water facilities materialise, it will take quite a long time before you succeed in educating the ordinary peasant. Therefore, the agriculture of this country would have to be thought of indigenously, in the light of what suits us best. Some *via media* between what the Western countries have done, and what countries like Japan are doing, some such *via media*, would have to be found out. We have got to remember that our agriculturists are very intelligent and are prepared to take on anything new and better. But what is lacking is our determined will, a will to approach and educate them through the proper Community Project people. Community Project people have been created only for this very purpose, to educate the farmers. But I must say without fear of contradiction that the Community Project organisation has become, in most of the villages, in the rural areas, the laughing stock of every body.

SHRI P. N. SAPRU : Quite true.

SHRI KHANDUBHAI K. DESAI: Now, under the able and efficient guidance of our young Food Minister this personnel, which is in a large number, for the time being unwanted, will be utilised very properly. If properly utilised, they can give fillip to agriculture.

(Time bell rings.)

Five minutes more please.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You have taken over twenty minutes.

THE MINISTER OF FOOD AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI C. SUBRAMANIAM) : He is a senior Member.

SHRI KHANDUBHAI K. DESAI: Only two minutes more, and I have done.

SHRI C. SUBRAMANIAM: Five minutes.

SHRI KHANDUBHAI K. DESAI: I have placed before this august House my humble view that in the next five years we may not become self-sufficient in the matter of food. According to me it will have to take more. Now keeping that in view, all the cities—whether the Chief Ministers like it or not—all the cities with a population of five lakhs and more should be cordoned off, that is, rationing would have to be done in cities with a population of five lakhs and more.

SHRI P. N. SAPRU: Three lakhs.

SHRI KHANDUBHAI K. DESAI: I should say five lakhs because I am a little wary. You are a radical man though older, I know, but I am a little conservative. After all it should be remembered that a yard stick decided on should apply uniformly throughout the country, whether it is one lakh and more, or fifty thousand and more, or twenty-five thousand and more, but you should not put into your mouth more than you can muck, because we have had our past experience. So let us give thought to and prepare ourselves from now on for a smooth passage taking a long-range view of the matter, and let rationing cover, to start with, cities with five lakhs and more. Now that will cover anywhere from fifteen million to twenty million people. It is those people who have got large purchasing power, and who create all these problems.

SHRI P. N. SAPRU: Quite right.

SHRI KHANDUBHAI K. DESAI: Now there is the State Trading Corporation. You have created all the structure\* institutions. All the institutions have been created but may I say with all humility that they have been created in a haphazard way and never looked after with a view to their

proper utilisation. We passed here the legislation for bringing into being the State Trading Corporation, and we all paid tributes to the then Minister who piloted the Bill and said that he had done a good job by going in for the State Trading Corporation. But how has State-trading fared? Therefore, all the instruments that you have created must be given life, and if some of the instruments that you have created are not working well, I would suggest your closing them down, and keep only those institutions that are worthy of retention by their utility. Therefore, rationing in cities with a population of five hundred thousand and more is a must, and our Chief Ministers of States, whether the States are surplus or deficit in food, must take to this step of rationing. Now rationing is not a happy state of affairs, it may not be good psychology, but then, in the present circumstances, they must all take to it whether they like it or not. The country should be viewed as a composite whole, and if there is scarcity of, or less food, it must be distributed equitably throughout the land. That is all I have to say. Madam, on this food situation. You may go on importing, but there is nothing like producing more in our own country. Thank you.

**श्री जगत नारायण (पंजाब) :** मैडम डिप्टी चैयरमैन, मैं राम रेड्डी जी की तक्रार सुनकर हैरान हूँ क्योंकि उन्हें आपोजीशन के लीडर श्री वाजपेयी और श्री डाह्याभाई पटेल जी ने जो यह कहा कि आज हम संसार में भीख मांग रहे हैं उससे उनको बड़ा गुस्सा आ गया। मुझे याद है कि पिछले सेशन में जब फूड समस्या पर बहस हो रही थी तब श्री राम रेड्डी जी ने बड़े-बड़े फिगरस दिये थे कि प्लानिंग कमिशन ने इतना खर्च किया जिससे हमारे मुल्क में इतना अनाज पैदा होगा। उस वक्त उन्होंने सरकार को कोसा था कि क्या वजह है कि इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी हमारे मुल्क में अनाज पैदा नहीं हुआ। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वे अपनी तक्रार को घर में जाकर पढ़ें कि उन्होंने पिछले मर्तवा क्या कहा था। मैं अपने फूट मिनिस्टर साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि

SHRI N. SRI RAMA REDDY: That was about the economics of agriculture, not the food situation. Today we are discussing the food situation.

**श्री जगत नारायण :** उस वक्त भी हम फूड मिनिस्टर पर बहस कर रहे थे।

SHRI S. S. MARISWAMY (MADRAS): Then he was speaking as an agriculturist and now he is speaking as a Congressman.

**श्री जगत नारायण :** मैं वर्जार साहिब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमें कितना अनाज चाहिये जिससे कि हिन्दुस्तान के लोगों को दो वक्त खाना मिल सके अपनी पैदावार के साथ-साथ? तो आज हालत क्या है? वर्ल्ड रेडक्रास ने अपील की है जो इस प्रकार है—

"World Red Cross Appeal for Food Aid to India : The International League of Red Cross Societies yesterday appealed to its members to supply powdered milk and other protein-rich foods to relieve the 'alarming' food situation in India."

"French Food Aid: France will gift powdered and condensed milk, vitamins and insecticides collectively valued at Rs. 1.6 crores to help India in its food crisis."

आज हमें कितने फूड की दरकार है जिसके लिए आज सारी दुनिया लगी हुई है अपील करने के लिए कि हिन्दुस्तान में फैमिन हो गया है और उसको किसी न किसी तरह से बचाओ। हमारे सेक्रेटरी जनरल उं थांट और डायरेक्टर जनरल फूड डिपार्टमेंट के श्री सेन ने भी अपील निकाली है :

"Tham and Sen Appeal for Food Aid to India : According to U Thant and Dr. Sen, 100 million people in seven large States have been affected by the food shortage. India requires from 11 million to 14 million tons of foodgrains and 130 thousand tons of powdered milk to overcome the shortage."

इसका मतलब यह है कि हमें 11 से 14 मिलियन टन फूड की जरूरत है। थार्डलैण्ड में जो हमारे सेक्रेटरीजयें हैं उनके बारे में एक खबर यह निकली है जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

"Smaller quantities may be available from the U.A.R., Argentina and Cambodia."

[ श्री जगत नारायण ]

The U.A.R. gave 35,000 tons last year though the deal was for 60,000 tons Altogether, India may be able to secure five to six lakh tons of rice this year as against about seven lakh tons in 1965."

10 मिलियन टन अनाज हमें अमरीका से मिल रहा है और इसी तरह से हम बर्मा से भी अनाज ले रहे हैं। इस तरह से हमें कुल कितना अनाज चाहिये इसके बारे में कुछ नहीं बतलाया गया है क्योंकि इस समय सारी दुनिया हमारे लिए अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई है और हम उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैडम, आप यह बात सुनकर हैरान होंगी कि एक तरफ तो यह सिचुएशन है और दूसरी तरफ पंजाब की यह हालत है कि यह मेरे पास 13 फरवरी का ट्रिब्यून पड़ा हुआ है और उसमें जो कुछ लिखा है आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :

"Wheat Glut at Moga while country suffers from shortage : Over three lakh maunds of wheat worth about Rs. 72 lakhs have accumulated here when certain States are suffering from an acute shortage of food. When so much wheat is available why it is not being procured by the State either for its own reserve stocks or for other States is a mystery. Reports are there that the stocks were kept in the hope of making money on the abolition of the Food Zones for which pressure is being now put on the Centre."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair]

इस सरकार को किस तरह समझाया जा सकता है, समझ में नहीं आता है : क्योंकि सरकार खुद महंगे दाम पर गल्ला बेचना चाहती है, अभी जालंधर की यह हालत है कि परसों वहां की मण्डी के लोग मिलने आये थे और कहने लगे कि आप जब पार्लियामेंट में फूड के मामले पर बहस हो तो यह बात कहिये। वे कहने लगे कि हमारी मण्डी में फूड नहीं तो करीब 2 करोड़ मन अनाज पड़ा हुआ है जिसमें गन्धम, मेज, बाजरा और चना शामिल है। इस समय वहां पर पोजीशन यह है कि फेयर प्राइस शाप्स

में गन्धम 64 रु० प्रति क्विंटल है और मार्केट में 59 रु० प्रति क्विंटल बिक रही है। यानी जो फेयर प्राइस शाप्स में जाकर अनाज खरीदता है उसको 64, 65 रुपये क्विंटल खरीदना पड़ेगा। यहां जहां तक मार्केट का ताल्लुक है उसके 58 से 60 रु० क्विंटल मिल सकता है। इस वक्त पंजाब की मार्केट में अनाज का ग्लट हो रहा है और इसकी वजह क्या है ? इसकी वजह साफ है कि यहां दिल्ली में राशनिंग हो गया है। पहले यहां पर स्मगल करके व्हीट और दूसरी चीजें ले आते थे और ऊंचे दामों में बेच दी जाती थीं। अब यहां पर अनाज की जरूरत नहीं है क्योंकि राशनिंग हो गया है। इसलिए मार्केट में जो स्टॉक आ रहा है उसको उठाया नहीं जा रहा है। आपने जो व्हीट जोन्स बनाये हैं वहां पर व्हीट सस्ता मिल रहा है और लोग खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन हम से कहा जाता है और दुनिया को परेशान किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान में फैंमिन हो रहा है और वहां पर लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। हमारे राम रेड्डी साहब चले गये और वे हमारे नेताओं की सच्ची बात सुनकर नाराज हो गये जब उन्होंने कहा कि हम भिखमंगे हो गये हैं। चीन की हालत यह है कि जो चीन हमारा दुश्मन है उसने अपने देश के बारे में क्या किया है और पैकिंग वाले हमारे बारे में यह कहते हैं :

"The result is to feed the malicious humour and propaganda of our ill-wishers all over the world. Radio Peking, for example, has dug up a decade-old Hindustani beggars song—'Bate. Roti De !'— from some film, and plays it frequently to malign us. Some graceless Yank—Francis E. Raterman, Director of the US Agency for International Development—has made the derisive statement that one Indian out of 23 is fed entirely by the PL-480 foodgrains."

आज जितनी इमेज श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बनाई थी पाकिस्तान से जंग करके, वह सारी इमेज हमारे फूड मिनिस्टर साहब खत्म कर रहे हैं। आपको यह बात

सुनकर हैरानी होगी कि पोप ने अपने श्रद्धालुओं की एक मीटिंग बुलाई और वर्षा के बीच आध घंटे तक हिन्दुस्तान में भुखमरी के बारे में तकरीर की। मैं आपको उस लेटर का मजमून पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो पोप को दो बच्चों ने हिन्दुस्तान के लोगों की मदद के लिए भेजा था :

*Pope Renews Plea to help India :* Renewing his plea for help for India, Pope Paul VI stood today at his studio window and publicly read a letter from two Italian youngsters who sent him their savings for the people of India. A down pour drench J 6,000 persons who stood in St. Peter's Square for the pontiff's Sunday noon blessing.

Vatican officials said the letter came from a boy and his sister, Emilio and Lucia, who wrote on behalf of themselves and a baby brother of a few months.

The officials did not identify the children of their city, but said they sent the Pope U few thousand lire' (1000 lire make about Rs. 7,601.)

'Listen to the letter' said the pope,

'Dear Holy Father : Papa told us about the troubles of the Indians and that you explained it is not possible to be good Christians if we do not help our poor brethren. So we have decided to send you the money we saved. Papa and Mamma said, it would be as if they had four children instead of three.'

इस तरह की हालत है और इस ढंग से हिन्दुस्तान के मुताल्लिक अनाज इकट्ठा किया जा रहा है और अनाज मंगाया जा रहा है। मेरे भाई श्री राम रेड्डी कह रहे हैं कि हम जानबूझ कर उनको बदनाम कर रहे हैं। हम यह कैसे न करें क्योंकि हिन्दुस्तान में इतना अनाज इकट्ठा है कि आप उस अनाज से सारे मुल्क का काम चला सकते हैं ? मैंने पिछली मतर्वा फिगर्स दिये थे कि हमारे मुल्क में 80 या 90 मिलियन टन अनाज पैदा होता है। एक पीड रोजाना प्रति आदमी के हिसाब से अगर खाना दिया जाय, जितना कि एक कैदी को मिलता है, तो हमारी सरकार ने पिछले साल मुल्क में जितना अनाज होने

के बारे में कहा था उसके मुताबिक हम 50 करोड़ आदमियों को खाना खिला सकते हैं और दो वक्त खाना लोग खा सकते हैं। तो मैं मिनिस्टर साहिब से यह पूछना चाहता हूँ कि जो अनाज हमारे मुल्क में था वह कहाँ चला गया है ? वाइस चेयरमैन साहिब, आप बुजुर्ग आदमी हैं और आपको पुराना जमाना याद होगा कि जब अंग्रेजों के जमाने में एक रैली ब्रदर्स हुआ करते थे। अब भी हैं मगर उस जमाने में उस फर्म की यह हालत थी कि सारे हिन्दुस्तान में उसकी वॉचेज थीं और सुबह उठ कर वे जिस भाव, जिस निरख पर, गंदुम खरीदा करते थे या दूसरी चीजें खरीदा करते थे, सारे हिन्दुस्तान में उन चीजों का वही निरख होता था। उसकी क्या वजह थी ? वजह यह थी कि वे सब से बड़े बायर थे। आज हमारी सरकार भी सब से बड़ी बायर है। वह बाहर से अनाज मंगाती है, स्टॉक भी करती है, सारी स्टेट्स की सरकारें भी खरीदती हैं। तो जब यह सरकार इतना अनाज खरीदती है तो क्यों यह रेट मुकर्रर नहीं करती है। यह भी रेट मुकर्रर करे जैसे रैली ब्रदर्स वाले किया करते थे। वाइस चेयरमैन साहिब, आपको याद होगा कि रैली ब्रदर्स यहाँ से अनाज खरीद कर बाहर के मुल्कों को भी भेजा करते थे। एक दफा फैमिन हुआ था तो हमारे एक शायर ने एक गीत गाया था। दाना-दाना उठा कर के रैली ब्रदर्स ले गये, इस किस्म का नज्म था। उसका मतलब यह था कि हमारे यहाँ मुल्क में फैमिन हुआ है क्योंकि रैली ब्रदर्स यहाँ से दाना-दाना उठा कर बाहर के मुल्कों में ले गये हैं। तो पहले हम इतना अनाज पैदा करते थे कि उसको हम अपने मुल्क में सप्लाई करते थे और बाहर भी भेजा करते थे। अब हमने तीन प्लान्स पर अरबों रुपया खर्च किया है, हमने बाहर से फर्टिलाइजर्स लिये और तमाम चीजें लीं। कर्जा तो आज हमारे हिन्दुस्तान के सिर पर इतना हो गया है कि जो बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होते ही उसके सिर पर पांच सौ रुपया कर्ज का हो जाता है, सारी दुनिया का।



### [श्री जगत नारायण]

जब तक वह बड़ा न हो, 500 रुपया कर्ज का उसके सिर पर आ जाता है, इतना हमने बाहर के मुल्कों से कर्जा ले रखा है। मुबह मेरी बहन कह रही थी कि हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें और हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिये कि तीन प्लान्स में हमने अरबों रुपया खर्च किया और हमारे मुल्क की कैसी तस्वीर दूसरे मुल्कों में दिखाई जा रही है। वहां छोटे-छोटे बच्चे चर्चों के सामने सन्दूक रख देते हैं और यह कहते हैं कि उसमें हिन्दुस्तान को अनाज भेजने के लिये पैसे डालो। आजादी के बाद यह बात पहली बार हम सुन रहे हैं। इससे पहले कभी हमने न इसे अखबारों में पढ़ा और न सुना। यह सोचना होगा कि यह सारी बात क्यों हुई। इसकी वजह यह है कि वोटों के लिये हमारी सरकार जो अनाज देहात में पड़ा हुआ है उसको निकलवाने की कोशिश नहीं करती है। जैसा कि मैंने आप से अर्ज किया कि आज पंजाब की मंडियों में ग्लट है। इतना अनाज वहां आ रहा है कि कोई उसे उठाने वाला नहीं है। वहां की सरकार भी उसको उठाने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि जिन प्राविसेज के पास जरूरत से ज्यादा अनाज है, वहां की सरकारों से सेंटर को कहना चाहिये कि वे उस अनाज को खरीद लें और फिर आपको मुहैया करे बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क का ढिंढोरा बजे और दो-दो चार-चार साल के बच्चे हिन्दुस्तान के लिये भीख मांगें। यह हिन्दुस्तान के नाम पर एक बहुत बदनुमा धन्वा है।

सवाल यह पैदा हुआ है कि हम खुद-कफील क्यों नहीं हो रहे हैं। आप यह सोचते हैं कि फर्टिलाइजर बाहर से आना चाहिये और उसके लिये करोड़ों रुपये के कारखाने लगाये जायें। मगर मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जो गोबर होता है उसका भी फायदा नहीं उठाया जाता है। हमारे पास जो बी० डी० ओ० हैं, ग्राम सेवक हैं, लेडी ग्राम सेविका हैं वे अगर देहात में जा कर

लोगों से कहें कि गोबर के उपले नहीं बनाना चाहिये, उसको जलाने के काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिये, तो हमारे गांवों में ही जितना मवेशियों का गोबर होता है उसी से मेन्योर का बहुत-सा काम हो सकता है। पहले जब कभी दस पन्द्रह साल के बाद कहल हुआ करता था तो जो हमारे बुजुर्ग थे वे इस तरह से अपनी पैदावार पैदा करते थे कि सारा देश कभी भूखों नहीं मरता था यह कभी नहीं हुआ कि कभी सारे हिन्दुस्तान में कहल पड़ गया हो। मुल्क के किसी कार्नर में कहल का अमर हुआ करता था, बाकी सारे हिन्दुस्तान में लोग ऐश व आराम से रहा करते थे। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जो मेन्योर की प्राब्लम है इसके लिये जब तक आप दूसरे मुल्कों से रुपया ले कर और कारखाने लगा कर मेन्योर पैदा न कर सकें तब तक कम-से-कम आपको जो हमारे देश में गोबर होता है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिये। इसके लिये जितने आपके बी० डी० ओ०, विलेज लेवल वर्कर और लेडी वर्कर हैं, उनसे आप कहिये कि वे देहात में जाकर के बहनों से और जमींदारों से कहें कि वे किस तरह से गोबर की मेन्योर को इस्तेमाल करें ताकि अनाज ज्यादा पैदा हो सके।

मैंने पिछले सेशन में भी यह अर्ज किया था कि लुधियाना में मेक्सिकन ह्वीट का तजुर्बा किया गया है। मेरे भाई अब्दुल गनी ने वह पढ़ कर सुनाया था कि मेक्सिकन ह्वीट का जो तजुर्बा किया गया उसमें उसकी सात गुना ज्यादा पैदावार हुई एक एकड़ में। अगर एक एकड़ में सौ मन पैदा होता था तो सात सौ मन पैदा हुआ। तो अगर हम मेक्सिकन ह्वीट का इस्तेमाल करेंगे और मेन्योर बगैरह का ठीक इन्तजाम करें तो इससे हमारी पैदावार बहुत बढ़ सकती है। फूड मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने सारी बातें पेश की और तजुर्बों की कामयाबी के बारे में उन्होंने उनको कितानें बगैरह भेजी।

फिर भी क्या बजह है कि हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तबज्जह नहीं देती है।

**श्री अर्जुन अरोड़ा ( उत्तर प्रदेश ) :** वह तजुर्बा जिसको अब्दुल गनी साहब ने भेजा था वह भी सरकारी पैसे और सरकारी मदद से हुआ था।

**श्री जगत नारायण :** मैं भी यह नहीं कह रहा हूँ कि वह प्राइवेट तरीके से किया गया। उसको अमेरिका वालों ने किया, फोर्ड फाउन्डेशन वालों ने वह तजुर्बा किया और सरकार की मदद से किया। मौलवी साहब ने वह तजुर्बा नहीं किया। न उनके पास कोई जमीन है और न मेरे पास कोई जमीन है जिसमें वह तजुर्बा किया जाता। वह तजुर्बा सरकार ने किया। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि मैक्सिकन व्हीट से अगर इतने दिनों में और जगह भी तजुर्बा किया जाता तो हमारी पैदावार काफी बढ़ सकती थी।

वाइस चेयरमैन महोदय, आप को याद होगा कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधान मंत्री थे उन्होंने अपनी कोठी में हल चलवा दिया था इसलिये कि वहाँ भी अनाज और सब्जी पैदा हों। उसके बाद भी देखिये कि हमारे कितने बज्जियों और कितने अमीर आदमियों की कोठियों में हल चला है। उनमें आज भी इतनी जमीन फालतू पड़ी हुई है कि उसको देख कर के आदमी हैरान हो जाता है। मुझे फार्मोसा जाने का मौका मिला। वाइस चेयरमैन महोदय, आप हैरान होंगे यह सुन कर के कि वहाँ जो रेलवे की डबल ट्रैक है उसमें भी लोगों ने खेती कर रखी है। जैसी यहाँ दिल्ली से जालन्धर तक डबल रेलवे लाइन है, वैसी ही जो वहाँ डबल लाइन है और जो रेलवे की प्रापर्टी है उसमें भी लोगों ने कास्त को हुई है। किसी ने उसमें आलू बो रखा है, किसी ने खूँब बो रखा और किसी ने कुछ बो रखा है। वहाँ सड़कों के पास और रेलवे लाइन के पास कुछ फीट जमीन छोड़ कर के बाकी सब ओर उन्होंने उपज के लिये इस्तेमाल

कर रखा है। यहाँ आप ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे और रोड से भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ कितनी ऐसी जमीन पड़ी हुई है जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है। अगर हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे और उसी तरह का इन्तजाम करवाये जैसा कि फार्मोसा और दूसरे मुल्कों में है तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे सामने दिक्कत है और आज जो बैगर्स बाउल ले कर के हमको दुनिया के सामने जाना पड़ रहा है, वह चीज खत्म हो सकती है और फिर हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं रहेगी।

इतना मैं और कहना चाहता हूँ कि इजराइल का छोटा-सा मुल्क है। वहाँ जब तमाम दुनिया के यहूदियों ने जा कर के देखा कि यह तो डिजर्ट है तो उन्होंने मेहनत करके यह किया कि उन्होंने दस साल में वहाँ लहलहाते खेत खड़े कर दिये। इसके लिये उन्होंने यह किया कि उन्होंने मेहनत की, पानी पहुँचाया और दूसरी बातें की। हमने अपने यहाँ भी करोड़ों रुपया डिजर्ट पर खर्च किया है, लेकिन हम आज तक उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं जितनी उस छोटे-से मुल्क ने हासिल की है जो आधे पंजाब के बराबर है। उन्होंने अपने मुल्क में डिजर्ट में लहलहाते खेत खड़े कर दिये हैं और किसी मुल्क के आगे वे अपना हाथ नहीं पसार रहे हैं। क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं कि राजपुताने में जितना डिजर्ट है उसको हम लहलहाते खेतों में बदल दें। हम उसको जरूर बदल सकते हैं बशर्ते कि हमारी सरकार उनसे मदद ले। आप इजराइल वालों से पूछिये कि उन्होंने किस हंग से अपने डिजर्ट को लहलहाते खेतों में तबदिल किया है। हमें उनसे मदद लेने में घबराना नहीं चाहिए।

मैं बैठ जाऊंगा एक मिनट में, बेशक घंटी न बजाए।

मैं यह कहना चाहता हूँ वाइस चेयरमैन महोदय कि जो हमारी पालिसी है वह दो जगह लैक करती है। एक तो प्रोक्वोरमेंट में।

[श्री जगत नारायण]

हम डरते हैं बड़े-बड़े लैंडलार्ड्स से प्रोक्योर करने में। उनसे प्रोक्योर किया तो बोटें नहीं मिलेंगी। लैंडलार्ड्स बड़े व्यापारी बन गए हैं और गांवों में स्टॉकिस्ट बन गए हैं। वे तब रिलीज करते हैं जब उनको पता लगे कि मार्केट में भाव कम हो जाएगा। जब पंजाब में बारिश हुई और दिल्ली में राशन हुआ तो सारा स्टॉक मंडियों में आ गया। आज हालत यह है कि प्राइसेज गिर रही हैं। 65 से 58-60 पर आ गई हैं। जरूरी यह है कि लैंडलार्ड्स से प्रोक्योर किया जाए, वेशक उनको नाराज करें।

दूसरी चीज में यह समझता हूँ कि जब तक हमारी सरकार स्टेट ट्रेडिंग नहीं करेगी, तब तक आप कभी भी हिन्दुस्तान को अपने पांवों पर खड़ा नहीं कर सकेंगे और हिन्दुस्तान के लोगों को खुराक मुहैया नहीं कर सकेंगे। स्टेट ट्रेडिंग करने से घबराना नहीं चाहिए। स्टेट ट्रेडिंग करके हिन्दुस्तान जो भिखारी बन गया है उसे बचा लेना चाहिए ताकि हम किसी के आगे हाथ न फैलाएं और अपने पांवों पर खड़े हों और अपने मुल्क के लोगों के मुँह में जो खुराक डालें वह अपनी पैदा की हुई खुराक हो।

SHRIMATI C. AM MANNA RAJA (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, this food problem has been getting the attention of this House and outside for a few months now. The problem is acute no doubt but to say that we are famine-stricken is an exaggeration. I was rather disappointed when the Minister, the other day, when there was a question as to how many States in the country were famine-stricken instead of saying we were really not famine-stricken, said that Madhya Prade-h, Maharashtra, Andhra Pradesh and several others were famine-stricken. I was really surprised. There may be shortage of foodstuffs; there may be drought; there may be shortfalls in expectations but actually we are not famine-stricken. And this picture has gone abroad also. It is a very sad thing that our Members day in and day out go on saying that we are beggars in spite of the

clear statement made by our Prime Minister. We are not beggars; we may take aid just like any other country. No country in the world is self-sufficient in everything. Some people have industries and no food, while some have food and no industries. Some have coal, some have steel and whatever is in short supply in a country is imported from outside. It is done everywhere. It is a well established practice; it is a well understood thing. So why do we say that we are beggars? It is not at all fair; it is not fair to our dignity; it is not fair to our conception of things. It is not right. The other day our Chairman was saying that a person asked another whether he had stopped beating his wife. If he does not say that he has never beaten her, the presumption is that it was being done. Like that when the question was put as to how many States in our country are famine-stricken, the Minister should have contradicted it and said: "There are shortages in some States; there are shortfalls in some districts; but actually there is no famine." Famine means dying of hunger. There is nothing like that in spite of some instances that were quoted by some. People probably have died of poverty but not of starvation. I do not know; I do not want to be contradicted. I want a statement from the Minister about this matter. Poverty, of course, we have got in our country. It is there and even after eighteen years of freedom we have not been able to wipe it out. It is a very sad thing. There are poor people; even if there is plenty going round, they cannot get two square meals a day. That is a different matter. We should all be very anxious to project a good picture of India in other countries and not disgrace ourselves by projecting our country in an undignified manner.

Now, the Food Corporation came into existence one year back. I do not know whether we are better off after that or not. Probably it looks very gloomy now because of the drought this year and it is unfortunate and but for this perhaps we would have given a better account of ourselves. Anyhow, "we cannot say that we have done very well with regard to either procurement or distribution. We must take into our hand full control or we must leave it without any control whatsoever. There is rationing in some areas; there is no rationing in some areas. There is statutory

rationing in some areas and there is informal rationing in some other areas and some people are left to get on as best as they can. I do not think this is really a satisfactory situation. Now, we have been crying hoarse for a very long time—not only now—that we have to produce more but what have we done to produce more ? Have we given sufficient incentives to the farmers to cultivate more or have we created conditions to drive away the small farmers to the cities to get a better living ? Actually I know the children of farmers and agriculturists feel that it is no use struggling hard throughout the year on the land to get a very small income at the end of the year. So they go away as clerks or even as attendants to get Rs. 100 to Rs. 150 in an office. That gives them Rs. 1,800 to Rs. 2,000 at the end of the year. If the farmer were to cultivate he has to struggle very hard in sun, in rain, against drought, against so many things. And there are man-made difficulties also. We say we supply them agricultural implements, fertilisers, loans, etc. but are they reaching them at all ? Or if at all they reach them, are they reaching them in time ? The other day one Punjabi gentleman was saying that these things do not go to the agriculturist but to the Aggarwal. This is a very sad state of affairs. Our co-operative societies do not function properly; our people are not honest; our people are not sincere—some of them of course—and so, the agriculturist suffers. For everything they have to buy they have to pay very high prices and they have to pay incentives to get loans, to get implements, fertilisers, etc. It is a very hard job for them. So they feel that it is better to go and work in a factory or in an office or anywhere else than struggling hard on one acre or two acres or even five acres. So better incentives must be given to them.

We have also been exaggerating the situation. When there is a shortage all of us must tighten our belts and adjust our food habits to the necessities of the times. Instead of that, what is the use of our friends from Kerala saying that they want rice and rice alone ? And what is the excuse given ? It is that they do not know how to make *chapatis*. Is it a very difficult thing ? In fact we all have learnt from the Nairs coming from Malabar. They all know it; it is not very difficult. It is quite easy. People who shout in the demonstrations can take it upon themselves to teach how to do this, how to make *chidpatii* in an attractive way so that the children do not dislike them. They can make it in a variety of ways.

In fact, I have been pained to find that even the Ministers are blaming the surplus areas, particularly Andhra, that we are not co-operating with the deficit States and particularly Kerala. We are having rationing and we are people who are not used to anything else except rice. But we are eating wheat. At least the people from Kerala know—what is that . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): All right. You can continue tomorrow.

SHRIMATI C. AMMANNA RAIA : Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 3rd March. 1966.